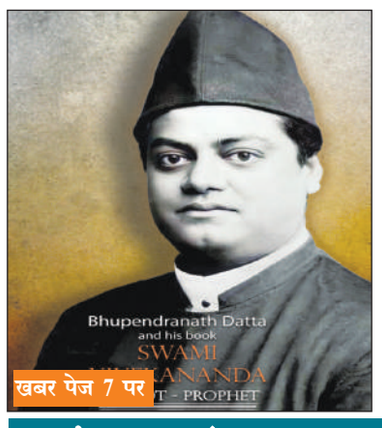

खबर पेज 7 पर

गंभीर समाचार

समय–समाज–संस्कृति

खबर पेज 8 पर

वर्ष -11 | अंक–18 | पाक्षिक समाचार पत्रिका | कोलकाता, सोमवार 1 – 15 दिसंबर 2025 | मूल्यः 5 रुपये | RNI No.WBHIN/2014/59321, ISSN No. 2456/3005 Kolkata | कुल पृष्ठ – 8

सुविचार

♦जो हमें तुम्हें मिला नहीं उस पर अफ़सोस करने के बजाय जो तुम्हारे पास है उसे मत गवाओं।

♦'जीवन में तुम्हें वही मिलता हैं जो तुम दूसरों को देते हो।'

शेरो-शायरी

♦किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंज़िल कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा।

♦अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख़्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें।

नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने खेला 'मास्टरस्ट्रोक'

♦ बंगाल में भी खिलेगा कमल?

♦ ममता बनर्जी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

निज संवाददाता : भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के मंत्री नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। जैसी उम्मीद थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। इधर, उत्तर प्रदेश के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक ऐलान होने के कुछ ही देर बाद बीजेपी ने जे पी नड्डा के उत्तराधिकारी का भी ऐलान कर दिया। पार्टी ने बिहार में चार बार के विधायक और मंत्री नितिन नवीन का नाम कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में घोषित कर दिया। बड़ी बात यह कि नितिन नवीन का नाम कहीं भी चर्चा में नहीं था। नवीन के नाम का ऐलान होते हुए बीजेपी ने कई नए रिकॉर्ड बनाने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। अगर वे पूर्णकालिक अध्यक्ष बनते हैं तो सबसे कम उम्र के होंगे। नितिन नवीन बीजेपी नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। नितिन नवीन की तरह बीजेपी ने पहले अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए जेपी नड्डा को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एनडीए की जीत के बाद कहा था कि गंगा मैया ने बंगाल का रास्ता बना दिया है। उन्होंने मंच से ऐलान किया था कि बीजेपी का अगला लक्ष्य बंगाल है। कायस्थ वर्ग से आने वाले नवीन बीजेपी के लिए बंगाल विधानसभा चुनावों में ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल कायस्थ वर्ग की काफी संख्या है। करीब 24 लाख मतदाता इस वर्ग के हैं। बंगाल में सबसे अधिक समय तक सीएम रहने वाले ज्योति बसु भी कायस्थ थे। ऐसे में बीजेपी के इस युवा नेता पर दांव खेलने को मिशन बंगाल से जोड़कर देखा जा रहा है। नवीन बेहद युवा और साफ छवि के नेता हैं। बंगाल के अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनावों में जब वह लोगों के बीच जाएंगे तो सवर्ण वोटरों में बीजेपी की अपील और बढ़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो बंगाल में गेम पलट सकता है।

बंगाल को लेकर दिया अहम बयान

भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने अपनी नियुक्ति को पार्टी कार्यकर्ताओं को समर्पित की है। इसी के साथ उन्होंने पद संभालते ही बंगाल को लेकर एक अहम बयान दिया। नितिन ने 2026 में बंगाल में होने वाले चुनावों को लेकर कहा कि पार्टी के लिए बंगाल चुनौती नहीं है। उन्होंने इस दौरान एनडीए गठबंधन को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। एनडीए गठबंधन ने हाल ही में बिहार चुनावों में शानदार जीत दर्ज की। भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का अच्छा प्रदर्शन रहा। अब एनडीए गठबंधन बंगाल चुनाव की तैयारी में है। इससे ठीक पहले नितिन नवीन ने कहा-पार्टी ने एक कार्यकर्ता पर भरोसा किया है। बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। एनडीए गठबंधन के लिए कोई चुनौती नहीं है। एनडीए गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। भाजपा के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन सोमवार को पटना स्टेशन के नजदीक स्थित प्रसिद्ध महावीर मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने बजरंगबली की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद मांगा। इस दौरान उनके साथ बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी थे। नितिन नवीन ने महावीर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पटना स्थित नवीन सिन्हा स्मृति पार्क पहुंचे और यहां अपने पिता, स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं को सिखाने, संवारने के साथ-साथ बढ़ाने का भी काम किया है।

विस चुनाव से पहले बंगाल में तेज हुई धार्मिक प्रतीकों की राजनीति

♦ बाबरी मस्जिद के बाद अब राम मंदिर बनाने की घोषणा

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले धार्मिक प्रतीकों की राजनीति तेज हो गई है। बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही दिन बचे हैं। इससे पहले राज्य में धार्मिक प्रतीकों की राजनीति एक बार फिर तेज होती दिखाई दे रही है। पिछले दिनों कोलकाता के साल्टलेक इलाके में कई जगह ऐसे पोस्टर देखे गए, जिनमें पूर्वी कोलकाता में अयोध्या की तर्ज पर विशाल राम मंदिर कॉम्प्लेक्स बनाने का दावा किया गया है। पोस्टरों में स्कूल, अस्पताल, ओल्ड-एज होम और अन्य वेलफेयर सुविधाओं से युक्त एक बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है। ये पोस्टर स्थानीय बीजेपी नेता और पार्टी की विधाननगर यूनिट के पूर्व अध्यक्ष संजय पोयरा के नाम से लगाए गए हैं। सिटी सेंटर, करुणामयी और अन्य प्रमुख इलाकों में लगे इन पोस्टरों में चार बीघा जमीन पर अयोध्या जैसे स्ट्रक्चर वाले राम मंदिर की बात कही गई है और लोगों से इस निर्माण के लिए एक-एक रुपये का योगदान देने की अपील की गई है। यह पोस्टर ऐसे समय में लगाए गए हैं जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर सस्पेंडेड टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के रेजिनगर में बाबरी मॉडल की मस्जिद की नींव रखी थी। यह कार्यक्रम भारी सुरक्षा के बीच हुआ था। उसी दिन जवाबी कदम के तौर पर बीजेपी ने मुर्शिदाबाद के ही बंजाटिया के मनिंद्र नगर में राम मंदिर के लिए भूमिपूजन कार्यक्रम आयोजित किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया। अब साल्टलेक के पोस्टर इस पूरे विवाद को राज्य के प्रशासनिक केंद्र के बेहद करीब ले आए हैं, जिससे यह बंगाल की राजनीति फिर गरमा सकती है। संजय पोयरा ने इसे राम राज्य की अवधारणा पर आधारित एक सोशल-स्पिरिचुअल मूवमेंट बताया। पोयरा ने कहा है कि राम के राज्य में राम का मंदिर जरूर होना चाहिए। विधाननगर में भी अयोध्या जैसा राम मंदिर बनेगा। हालांकि, जमीन की लोकेशन को लेकर उन्होंने कोई जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि पहले ही कई लोग जमीन, निर्माण सामग्री और यहां तक कि मूर्तियां दान करने की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से स्थान बताते ही रुकावटें खड़ी की जा सकती हैं। पोयरा ने घोषणा की कि भूमिपूजन और शिलान्यास 26 मार्च, यानी राम नवमी के दिन सुबह 10 बजे आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अगर लोग मंदिर निर्माण के लिए 1 रुपये का दान देना चाहें, तो वे इसे खुशी-खुशी स्वीकार करेंगे। पोस्टरों में यह दावा भी किया गया है कि प्रस्तावित कॉम्प्लेक्स में गरीबों के लिए अस्पताल, बच्चों के लिए स्कूल,ओल्ड-एज होम और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम होंगे। पोयरा के अनुसार यह उनके राम राज्य के विज़न का हिस्सा है, जिसमें भक्ति और जनसेवा को एक साथ रखा गया है। उधर, विधाननगर सिविक अथॉरिटी ने इस पूरे मामले पर अब तक कोई बयान नहीं दिया है और यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि इस तरह के निर्माण के लिए उन्हें औपचारिक आवेदन मिला है या नहीं।

कोलकाता में 7 दिसंबर को 5 लाख 60 हजार से अधिक लोगों ने किया सामूहिक गीता पाठ

ब्रिगेड परेड ग्राउंड बना आध्यात्मिक ऊर्जा का महासागर

ड़ा. अरविंद सेठ

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के प्रतिष्ठित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 7 दिसंबर 2025 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, जब 5 लाख 60 हजार से अधिक लोगों ने एक साथ श्रीमद् भगवद् गीता का पाठ किया। ''पंच लक्खो कोंठे गीता पाठ'' (पांच लाख कण्ठों में गीता पाठ) नामक यह आयोजन देश के अब तक के सबसे बड़े सामूहिक गीता पाठ कार्यक्रमों में शामिल हो गया।

आयोजन और नेतृत्व

इस विराट आध्यात्मिक समारोह का संचालन 'सनातन संस्कृति संसद' द्वारा किया गया। देशभर के विविध मठों, आश्रमों और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े संत-महात्माओं ने इसकी शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम के सभाधिपति भारत सेवाश्रम संघ के प्रसिद्ध सन्यासी पद्मश्री स्वामी प्रदीप्तानंद महाराज जी थे। इस विशाल आयोजन सभा की अध्यक्षता महान गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने की।

कार्यक्रम की रूपरेखा

सुबह 9:00 बजे वैदिक मंत्रोच्चार और भक्तिगीतों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। 10:00 आरती का विशेष आयोजन किया गया था। आरती के बाद सुबह 10:30 बजे गीतापाठ शुरू हुआ। यह दोपहर 12:30 बजे तक चला। इसमें विशाल जनसमूह ने एक स्वर में गीता के प्रथम अध्याय, नवम अध्याय व अठारहवें अध्याय का सामूहिक पाठ किया। पूरा मैदान आध्यात्मिक ऊर्जा, शांति और भक्ति की भावना से परिपूर्ण दिखाई दे रहा था। फिर मंच पर मौजूद आयोजकों और प्रमुख सदस्यों ने यहां उपस्थित लोगों को संबोधित किया।

उद्देश्य और संदेश

आयोजकों ने स्पष्ट किया कि इस कार्यक्रम का मूल ध्येय

* सनातन धर्म की मूल चेतना को जन-जन तक पहुंचाना
* गीता के सार्वभौमिक और व्यावहारिक संदेशों को समाज में प्रतिष्ठित करना
* युवा पीढ़ी को भारतीय सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना
* एकता, सद्भाव और आध्यात्मिक जागरण को बढ़ावा देना

देश-विदेश से उमड़ा जनसागर

इस दिन ब्रिगेड मैदान पर एकत्र लोगों की भीड़ केवल बंगाल तक सीमित नहीं थी। ओडिशा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बांग्लादेश और नेपाल सहित कई स्थानों से श्रद्धालु समूहों में पहुंचे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मभूषण साध्वी ऋतंभरा और बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी शामिल हुए। बंगाल के राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी सहित भाजपा के कई सांसद, विधायक व नेताओं ने उपस्थित होकर सामूहिक गीता पाठ में हिस्सा लिया।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

यह आयोजन राजनीतिक रूप से भी चर्चाओं में रहा। एक दिन पहले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के मॉडल वाली मस्जिद के शिलान्यास के बाद राज्य का माहौल गर्माया हुआ था, ऐसे में यह गीता पाठ कार्यक्रम बंगाल की सामाजिक-सांस्कृतिक धारा में एक अलग ही संदेश के रूप में देखा गया।

मुख्य संबोधन

बागेश्वर धाम के पूज्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने संबोधन में कहा-कोलकाता। आमी तुमाके बहुत भालो बासी। आज हमें देखकर खुशी है कि कोलकाता के पत्ता-पत्ता में भगवा लहरा रहा है। कोलकाता की मां काली की धरती आज लाखों लोगों के एक साथ गीता पाठ से सौभाग्यशाली हुई है। आज यहां देखकर ऐसा लग रहा है मानो हिंदू जग गया है। उन्होंने हिंदुओं से एक होने का आह्वान करते हुए कहा कि गीता हमारी शान है। भारत की पहचान है। साध्वी ऋतंभरा ने अपने संबोधन में कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से सुंदरबन तक हिंदू राष्ट्र की गूंज होनी चाहिए। बंगाल के राज्यपाल डॉ.सी. वी.आनंद बोस ने अपने संबोधन में भारत की युवा पीढ़ी में श्रीकृष्ण और अर्जुन की भांति कर्म करने का संदेश दिया। भारत के नवनिर्माण में अपनी सेवा देने के लिए तत्पर करने हेतु उन्होंने विशेष आवाहन किया। ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि बंगाल में पहली बार 2022 में एक साथ पांच हजार लोगों के साथ गीता पाठ के आयोजन की शुरुआत हुई थी जो अब पांच लाख लोगों तक पहुंच गई है। उन्होंने हिंदुओं से जागने की अपील करते हुए हिंदू राष्ट्र का जयघोष किया। उन्होंने कहा कि बंगाल संत परंपरा की भूमि रही है। राष्ट्रगान व राष्ट्र गीत भी बंगाल की देन है।

बीजेपी-आरएसएस बिहार चुनाव सफलता से सीख लेकर यूपी में बना रहे चुनावी मॉडल

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी एक साल से ज्यादा समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां अब से ही पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं। बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने चुनाव की तैयारियों को लेकर तेज़ी से काम शुरू कर दिया है। बिहार चुनाव में मिली बीजेपी की जबरदस्त सफलता ने संघ और पार्टी दोनों को यूपी में रणनीति बनाने के लिए प्रेरित किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की सीटें अपेक्षा से कम रही थीं, और इसके पीछे विपक्षी समाजवादी पार्टी की बढ़ती ताकत और स्थानीय मुद्दों की भूमिका थी। यही वजह है कि अब संघ और बीजेपी ने यूपी में बिहार मॉडल को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष, संघ के सरकार्यवाह अरुण कुमार और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठकों में यूपी के प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने जिले में संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ नियमित रूप से समन्वय बैठक करें। स्थानीय मुद्दों, विकास कार्यों और कमजोर कड़ियों की पहचान के लिए विस्तृत सूची तैयार की जा रही है, ताकि समय रहते सुधार किया जा सके। संघ अपने शताब्दी वर्ष के तहत बड़े पैमाने पर हिंदू सम्मेलनों की श्रृंखला आयोजित करने जा रहा है, जिनमें लखनऊ में प्रस्तावित विराट हिंदू सम्मेलन भी शामिल है, जो चुनावी तैयारियों का हिस्सा माना जा रहा है। बिहार चुनाव में संघ की रणनीति बेहद प्रभावी रही। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 42.56 फीसदी था, जो 2025 में बढ़कर 48.44 फीसदी तक पहुंच गया। जेडीयू का वोट शेयर 32.83 फीसदी से बढ़कर 46.2 फीसदी और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी का वोट शेयर 10.26 फीसदी से 43.18 फीसदी तक पहुंच गया। यह सफलता केवल चुनावी मशीनरी की नहीं बल्कि संघ की लंबी और लगातार मेहनत का परिणाम थी। संघ ने हर जिले में कम से कम 100 स्वयंसेवकों को तैनात किया था और छात्र इकाई एबीवीपी के 5,000 कार्यकर्ताओं को पांच-पांच की टोली बनाकर पूरे बिहार में काम सौंपा गया था। चुनाव प्रचार के दौरान ये कार्यकर्ता शोर-शराबे से दूर रहकर जमीनी स्तर पर संगठनात्मक काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में भी संघ

इसी मॉडल को अपनाने की योजना बना रहा है। यूपी के पश्चिमी हिस्सों और मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में बीजेपी के लिए चुनौती बनी रहती है। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में संघ ने हिंदू वोट को एकजुट रखने की कोशिश की थी, जिसके परिणामस्वरूप 32 सीटों में से 21 पर एनडीए उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। यूपी में भी संघ इसी रणनीति को लागू करने की तैयारी में है। विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए बीजेपी को राजनीतिक समझौते करने पड़ सकते हैं, जैसे कि बीएसपी से कथित सहयोग। यूपी में भी संघ और बीजेपी की रणनीति यही होगी कि हिंदू वोट को बांटे बिना संगठन और विकास के एजेंडे को मजबूत किया जाए। बीते हफ्तों में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ आए और दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में भाग लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच साझा किया और बीजेपी के संगठनात्मक कार्यों पर चर्चा की। इसके अलावा, बीएल संतोष की संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ लंबी बैठक हुई, जिसमें आगामी चुनाव की तैयारियों और संगठनात्मक समन्वय पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार और संगठन दोनों में बड़े फेरबदल पर भी विचार किया जा रहा है। कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारियों में बदलाव और नए चेहरे शामिल करने की संभावना है। बीजेपी को जल्द ही नया अध्यक्ष भी मिल सकता है जो चुनावी रणनीति को और तेज करेगा। संघ और बीजेपी की रणनीति केवल संगठनात्मक नहीं है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रणनीति पर भी केंद्रित है। युवाओं, छात्रों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समूहों से जुड़ाव बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। हिंदू संस्कृति, पहचान और सामाजिक समरसता के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जा रही है।

संघ का उद्देश्य है कि विकास, सुशासन और हिंदुत्व के मुद्दों को जनता के सामने स्पष्ट रूप से रखा जाए। यह रणनीति बिहार मॉडल की तरह उत्तर प्रदेश में भी लागू की जा रही है, ताकि विपक्षी मतों को विभाजित किया जा सके और बीजेपी को अधिक सीटें मिलें। विशेषज्ञों का मानना है कि यूपी विधानसभा चुनाव सिर्फ राजनीतिक मुकाबला नहीं होगा, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर भी टकराव का मैदान होगा। विकास बनाम पहचान, जाति बनाम हिंदू एकजुटता, तथा सुशासन बनाम राजनीतिक विरोधी गठबंधन की लड़ाई के रूप में यह चुनाव सामने आएगा। संघ और बीजेपी की योजना यह है कि स्थानीय स्तर पर मजबूत संगठन, विकास और हिंदूसामूहिकता के संदेश के जरिए 2027 में सत्ता सुनिश्चित की जाए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में संघ की भूमिका लंबे समय से महत्वपूर्ण रही है। अब बिहार चुनाव से मिली सीख और रणनीति को यूपी में लागू करने की योजना ने मिशन यूपी को और स्पष्ट रूप दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और संघ की यह रणनीति ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रभावी होने की उम्मीद है। विपक्ष के लिए चुनौती यह होगी कि वह जाति और स्थानीय समीकरणों के जरिए संघ और बीजेपी की योजनाओं का मुकाबला कर सके। बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनावी अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि संघ और बीजेपी की रणनीति सिर्फ वोट बैंक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापक संगठनात्मक तैयारी और सामाजिक संदेश पर आधारित है। यूपी में भी संघ और बीजेपी यही मॉडल लागू करेंगे। इसके तहत स्थानीय मुद्दों की पहचान, कमजोर क्षेत्रों में सुधार, युवाओं और छात्रों का सक्रियकरण, हिंदू पहचान और विकास एजेंडा प्रमुख होंगे। 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी और संघ की यह रणनीति निर्णायक साबित हो सकती है, क्योंकि यह रणनीति जमीनी स्तर पर गहराई तक काम करती है और विपक्षी मतों को विभाजित करने की क्षमता रखती है। बहरहाल, यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए मिशन यूपी पहले से ही सक्रिय हो चुका है। संघ और बीजेपी ने बिहार मॉडल से सीख लेकर स्थानीय स्तर पर रणनीति बनाई है, जिसमें संगठनात्मक समन्वय, विकास और हिंदूसामाजिक संदेश को प्रमुखता दी जा रही है। विपक्ष के लिए यह चुनौतीपूर्ण होगा कि वह संघ और बीजेपी की व्यापक तैयारी का मुकाबला कर सके। आने वाला समय यह तय करेगा कि यूपी में मिशन यूपी कितना सफल होता है और क्या संघ और बीजेपी अपनी रणनीति के जरिए सत्ता में मजबूत स्थिति बनाए रख पाते हैं।

अगले वर्ष स्कूलों में सिर्फ छह दिनों की मिलेंगी गर्मी की छुट्टियां

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लिया फैसला

निज संवाददाता : अगले अकादमिक वर्ष से स्कूलों की छुट्टियों में कटौती की जाएगी। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) ने एक बड़ा फैसला लिया है। अगले अकादमी वर्ष में गर्मी की छुट्टियां सिर्फ 6 दिन की होंगी। बोर्ड ने मंगलवार को अगले अकादमिक वर्ष के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया। इसमें दिखाया गया है कि वहां गर्मी की छुट्टियों के दिन तय कर दिए गए हैं। छुट्टियों के दिन 11 मई से 16 मई तक चुने गए हैं। यानी, 2026 में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्र-छात्राओं को सिर्फ 6 दिन की गर्मी की छुट्टियां मिलेंगी। इस बारे में बोर्ड का तर्क है कि नियमों के मुताबिक, एक साल

में स्कूलों को 65 छुट्टियां दी जाती हैं। कई नई छुट्टियां दी जा रही हैं। इस वजह से गर्मी की छुट्टियों में कटौती करनी पड़ी है। हालांकि, शरद महोत्सव के मौके पर 28 दिन की छुट्टियां दी गई हैं, जिसमें दुर्गा पूजा पर फोकस किया गया है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष रामानुज गंगोपाध्याय माध्यमिक परीक्षाओं की देखरेख के लिए उत्तर बंगाल में हैं। हालांकि उनका जवाब नहीं मिल पाया, लेकिन बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि गर्मी की छुट्टियों में कटौती को लेकर राज्य सरकार ने कई नई छुट्टियों की घोषणा की है। जैसे, गुरु रविदास की जयंती, वीर चिलाबाई की जयंती, ईस्टर सैटरडे, होली दिवस, करम पूजा जैसे दिनों में स्कूल की छुट्टियां दी जाती हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ज़्यादा गर्मी के कारण लगभग हर साल स्कूली छात्रों को अतिरिक्त छुट्टियां देती है। स्कूलों को वह छुट्टी माननी पड़ती है। पिछले कई सालों से गर्मी में पारा चढ़ जाता है। राज्य के कई जिलों में भीषण गर्मी के हालात बन जाते हैं। तेज़ गर्मी में स्कूलों में क्लास करते समय छात्रों के बीमार होने की संभावना रहती है। इसीलिए स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां बढ़ा दी जाती हैं।

2026 के विधानसभा चुनाव में बाहरी नेताओं के हाथ में रहेगी भाजपा की कमान

पार्टी की प्रदेश इकाई में बढ़ रहा है गुस्सा

निज संवाददाता : राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत इस महीने से बंगाल भाजपा का संगठन दूसरे राज्यों के गैर-बंगाली नेताओं के नियंत्रण में चला जाएगा। दूसरे राज्यों के नेता मंडल-जिले से लेकर राज्य स्तर तक संगठन और प्रचार का काम देखेंगे। यानी पूरी स्टीयरिंग (कमान) उन्हीं के हाथ में होगी। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में बुरी हार के बाद प्रदेश भाजपा के अंदर यह सवाल उठा है कि गैर-बंगाली लीडरशिप की मॉनिटरिंग से बंगाल चुनाव में पार्टी को कितनी सफलता मिलेगी? दूसरे राज्यों के नेता बंगाल की जनता का मन कितना समझ पाएंगे? अब 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के असली खेमे के नेता और कार्यकर्ता यह सवाल फिर उठा रहे हैं। भगवा खेमे के एक बड़े हिस्से में शक है कि केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर

लगभग पूरी चुनावी जिम्मेदारी गैर-बंगाली नेताओं को सौंप दी है। सवाल उठता है कि क्या दूसरे राज्यों के नेता बंगाल की जनता का मन समझ पाएंगे? सूत्रों के मुताबिक, पार्टी में कोई पद न होने के बावजूद केके उपाध्याय फिलहाल राज्य भाजपा की चुनावी रणनीति का हर कदम तय कर रहे हैं। वे ऐसे संगठक हैं जो राजस्थान में सक्रिय थे और बाद में उत्तर प्रदेश में काम किया दिल्ली के नेताओं के बीच भरोसेमंद व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। बड़ी बात यह कि वे अमित शाह से लेकर केंद्रीय पर्यवेक्षकों के ज़िलों के दौरे का कार्यक्रम बना रहे हैं।
पार्टी के एक प्रदेश नेता के मुताबिक, यह केंद्रीय नेता प्रदेश नेताओं को बताए बिना कई फ़ैसले ले रहा है। इस वजह से, स्थानीय नेतृत्व लगभग उन पर निर्भर हो गई है। फिर से, सुनील बंसल, अमित मालवीय और मंगल पांडे, ये तीनों नेता जो पार्टी के संगठन मामलों के प्रभारी हैं, सभी दूसरे राज्यों के नेता हैं। भूपेंद्र यादव और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब को चुनाव कमेटी का नया प्रमुख बनाया गया है। नतीजतन, भाजपा के अंदरखाने एक बड़ा सवाल यह है कि,''पार्टी को अचानक बंगाल की पॉलिटिकल असलियत जाने बिना बाहर के कुछ नेताओं के कहने पर चलना पड़ रहा है। इसके अलावा, इस महीने से दूसरे राज्यों से कई केंद्रीय नेता और मंत्री राज्य में आ रहे हैं। वे अलग-अलग ज़ोन के हिसाब से आएंगे। वे मंडल स्तर तक चुनाव के प्रभारी होंगे। आंध्र प्रदेश-दिल्ली-उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक के नेता वोटों को संभालने आ रहे हैं। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा-यह मानना मुश्किल है कि हम अपने ही राज्य में पैरासाइट्स की तरह लड़ेंगे, और दूसरे राज्यों की लीडरशिप डंडा चलाएगी। हमें बंगाल की राजनीतिक, बंगाल के लोगों के मन को समझने की ज़रूरत है।

23 दिसंबर से शुरू होगा शताब्दी पुराना शांतिनिकेतन पौष मेला

देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक हर वर्ष इस मेले में शामिल होते है

निज संवाददाता : शांतिनिकेतन की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक, शताब्दी पुराना परंपरागत पौष मेला इस वर्ष 23 दिसंबर से आरंभ हो रहा है। यह मेला 6 दिनों तक चलेगा। मेले को सफल करने के लिए युद्धस्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विश्वभारती प्रशासन और शांतिनिकेतन ट्रस्ट के अधिकारी लगातार मैदान का निरीक्षण कर रहे हैं। बड़ी बात यह कि कई वर्षों बाद पौष मेला बड़े पैमाने पर

आयोजित होने जा रहा है, जिससे व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। गौरतलब है कि रवींन्द्रनाथ टैगोर के शांतिनिकेतन का यह प्रमुख उत्सव अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक हर वर्ष इस मेले में शामिल होते हैं। भुवनडांगा के पूर्वपल्ली मैदान में लगने वाले इस मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। विश्वभारती प्रशासन, शांतिनिकेतन ट्रस्ट और विश्वभारती कर्मचारी परिषद लगातार बैठकों के माध्यम से आयोजन संबंधी कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। मैदान की सफाई और अन्य प्रारंभिक कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं।

10वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने दी नीतीश कुमार को बधाई

कहा-यह भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में एक अद्वितीय उपलब्धि

निज संवाददाता: हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बन गई है। 2025 के विधानसभा चुनाव में एक तरफ जहां बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भी 85 सीटें मिलीं। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ पटना के गांधी मैदान में ली। 10वीं बार शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार को लगातार बधाई और शुभकामनाएं मिल रही हैं। इसी क्रम में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके लिए बधाई दी है। नीतीश कुमार के लिए कहा गया है-यह देश के लिए गौरव की बात है कि वर्ष 1947 से लेकर 2025 तक, आप (नीतीश) देश के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने दस बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यह भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में एक अद्वितीय उपलब्धि है। यह

असाधारण उपलब्धि आपके अटूट समर्पण, दूरदर्शी नेतृत्व और बिहार की जनता का आप पर विश्वास और प्रशंसा को दर्शाती है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने कहा-लगातार दस बार राज्य का नेतृत्व करना लोकतांत्रिक इतिहास में एक दुर्लभ उपलब्धि है। यह न केवल एक उल्लेखनीय व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का क्षण भी है। शासन, विकास, सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक स्थिरता के प्रति आपका यह निरंतर प्रयास लाखों लोगों को प्रेरित करता रहेगा। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सूचित किया है कि इस अनुकरणीय और ऐतिहासिक उपलब्धि के सम्मान में औपचारिक रूप से नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार का नाम अपनी प्रतिष्ठित वैश्विक सूची में शामिल कर आपको आधिकारिक प्रमाण-पत्र समर्पित करने पर खुद को गौरवान्वित महसूस करेगा। बता दें कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन एक अग्रणी वैश्विक संस्था है। यह असाधारण विश्व रिकॉर्डों और उल्लेखनीय समावेशनों को मान्यता देने और पंजीकृत करने के लिए समर्पित है। यह संस्था दुनिया भर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, संस्थानों और ऐतिहासिक स्थलों की उल्लेखनीय उपलब्धियों, सांस्कृतिक विरासत और योगदानों का सम्मान करता है।

शहीद मातंगिनी हाजरा को लेकर भाजपा व टीमसी के बीच शुरू हुआ नया विवाद

निज संवाददाता : भाजपा और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बीच एक नया विवाद शुरू हो गया है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने इस सप्ताह की शुरुआत में राज्यसभा में कहा कि प्रसिद्ध बंगाली स्वतंत्रता सेनानी मातंगिनी हाजरा ने मुस्लिम होते हुए भी वंदे मातरम का नारा लगाया था। शर्मा की इस टिप्पणी पर टीएमसी खेमे ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा को बांग्ला विरोधी और बाहरी करार दिया। इस विवाद का फायदा उठाते हुए पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी ने अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा पर अपना हमला तेज कर दिया है। शर्मा की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि एक भाजपा नेता ने कहा कि मातंगिनी हाजरा मुस्लिम थीं। क्या आप (भाजपा) बंगाल को जानते भी हैं? मालूम हो कि मातंगिनी हाजरा उन अनेक महिलाओं में से थीं जिन्होंने महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के आह्वान का जवाब दिया। सितंबर 1942 में, 73 वर्षीय हाजरा ने लगभग 6,000 प्रदर्शनकारियों के जुलूस का नेतृत्व किया। इस जुलूस में अधिकतर महिलाएं थीं।

बंगाल में सात महीने बाद वक्फ संशोधन कानून लागू

पहले ममता बनर्जी ने खुलकर किया था कानून का विरोध

निज संवाददाता: ममता बनर्जी सरकार ने आखिर केंद्र का नया वक्फ संशोधन कानून राज्य में लागू कर दिया है। मालूम हो कि सात महीने के बाद बंगाल में इस कानून को लागू करने का ऐलान किया गया। इससे पहले केंद्र के नए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का ममता बनर्जी ने महीनों तक विरोध किया। उन्होंने यहां तक कहा था कि गोली मार दो लेकिन मैं पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने दूंगी। फिर अब अचानक उन्होंने गुपचुप तरीके से इस कानून को लागू कर दिया। मालूम हो कि 82,000 वक्फ संपत्तियों की जानकारी 5 दिसंबर की समय सीमा तक केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश जारी किए थे। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 इस साल अप्रैल में संसद के दोनों सदनों ने पारित किया था। पिछले दिनों सभी जिलाधिकारियों को लिखे एक पत्र में पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास विभाग के सचिव पीबी सलीम ने राज्य की वक्फ संपत्तियों की जिलेवार जानकारी निर्धारित समय सीमा तक केंद्रीय पोर्टल,umeedminority.gov.in पर अपलोड करने के निर्देश जारी किए। इस

फैसले को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कानून का खुलेआम विरोध किया था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि वह राज्य में नए अधिनियम को लागू नहीं होने देंगी। इसके अलावा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा विधेयक पेश किए जाने के बाद राज्य में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। कानून पारित होने के कुछ दिनों बाद 9 अप्रैल को जैन समुदाय के एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं बंगाल में वक्फ संशोधन अधिनियम को लागू नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें फूट डालो और राज करो की इजाज़त नहीं दूंगी। यहां 33 फीसदी मुसलमान हैं। वे सदियों से यहां रह रहे हैं। उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने कहा था कि मुझे गोली मार दो, फिर भी बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने दूंगी। संशोधित कानून के अनुसार वक्फ बोर्ड और न्यायाधिकरणों में गैर-मुस्लिम सदस्य होंगे।
अगर किसी संपत्ति पर वक्फ होने का दावा किया जाता है, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय सरकार लेगी। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार इस कानून के खिलाफ अदालत भी गई, लेकिन उसे अनुकूल फैसला नहीं मिला। संशोधित अधिनियम की धारा 3बी में कहा गया है कि देश भर में सभी पंजीकृत वक्फ संपत्तियों की जानकारी छह महीने (5 दिसंबर,2025) के भीतर केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए।

आवारा कुत्तों ने पेश की करुणा की अनूठी मिसाल

नवजात की बचाई जान, सातभर की रखवाली बच्ची के लिए पूरी रात कुत्ते न भौंके और न ही हिले

निज संवाददाता : बंगाल के नवद्वीप शहर में कुत्तों ने करुणा की अनूठी मिसाल पेश की। यहां आवारा कुत्तों ने एक नवजात बच्ची की जान बचाई। दरअसल देर रात, जब एक बच्ची शौचालय के पास सड़क पर लावारिस पड़ी थी तो कुत्तों के एक झुंड ने उसे घेर लिया। वे बच्ची के आसपास खड़े रहे, जैसे उसकी रखवाली कर रहे हों। सुबह जब एक महिला वहां पहुंची, तो कुत्तों ने उसे रास्ता दिया और महिला ने बच्ची को बचाया। महिला ने बच्ची उठाया तो उनका दिल कांप उठा।
उसने कहा कि जिन कुत्तों को हम अक्सर पत्थर मारकर भगाते हैं, उन्होंने वो किया जो शायद कई इंसान भी नहीं करते। उन्होंने इस बच्चे को जीवित रखा। यह घटना नवद्वीप के स्वराजपुर रेल कॉलोनी में हुई। राधा भौमिक ने बताया कि रात के अंधेरे में कोई नवजात बच्ची को शौचालय के पास छोड़ गया था। कुछ ही घंटों की यह बच्ची अकेली था, लेकिन आवारा

कुत्तों के एक झुंड ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। कुत्तों ने बच्ची को चारों ओर से घेर लिया और उसकी रखवाली करने लगे। वे न तो भौंक रहे थे और न ही हिल रहे थे, जैसे उन्हें पता था कि बच्ची को उनकी जरूरत है। सुबह जब मैं शौचालय की ओर गई, तो मैंने कुत्तों को देखा। कुत्ते थोड़ा हट गए, जिससे मुझे बच्ची दिखाई दी। राधा ने कहा कि ये कुत्ते, जिन्हें हम अक्सर भगाते हैं, उन्होंने वो किया जो कई इंसान नहीं करते। उन्होंने बच्चे को जिंदा रखा। मैंने तुरंत बच्चे को गोद में उठाया और मदद के लिए चिल्लाईं। राधा की आवाज सुनकर उनकी भतीजी-बहू प्रीति भौमिक दौड़कर आईं और बच्ची को महेशगंज अस्पताल ले गईं। वहां से डॉक्टरों ने बच्ची को कृष्णानगर सदर अस्पताल भेज दिया। डॉक्टरों ने बच्ची के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई। सिर पर जो खून था, वह जन्म के समय का लग रहा था। पुलिस का कहना है कि बच्ची को जन्म के तुरंत बाद छोड़ दिया गया था। पुलिस और चाइल्डलाइन के कर्मचारियों ने जांच शुरू कर दी है और बच्चे की सुरक्षा और देखभाल के लिए बाल कल्याण समिति से संपर्क किया है।

युवा भारती घटना की अलग जांच की मांग को लेकर हाई कोर्ट में दो जनहित याचिका

निज संवाददाता : सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में दो जनहित याचिका (पीआईएल) फाइल की गईं, जिनमें युवा भारती क्रीड़ांगण (साल्टलेक स्टेडियम) घटना की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की बनाई कमेटी को चुनौती दी गई है। केस करने वालों का कहना है कि राज्य की बनाई कमेटी के पास जांच का कोई अधिकार नहीं है। सही जांच के लिए अलग कमेटी की जरूरत है। इन दोनों केस की सुनवाई इसी हफ्ते होने की संभावना है।युवा भारती घटना की जांच के लिए ममता की बनाई कमेटी के प्रमुख रिटायर्ड जस्टिस असीम कुमार रॉय हैं। इसके अलावा मुख्य सचिव मनोज पंत और गृह सचिव नंदिनी चक्रवर्ती भी कमेटी में हैं। राज्य के विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस कमेटी के अधिकार को चुनौती देकर कोर्ट का ध्यान खींचा है। वकील सब्यसाची चटर्जी ने भी अलग-अलग हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजॉय पाल और जस्टिस पार्थसारथी सेन की डिवीजन बेंच का ध्यान खींचा है। दोनों का कहना है कि राज्य की बनाई कमेटी सही जांच नहीं कर पाएगी। इसलिए कोर्ट को एक अलग जांच कमेटी बनानी चाहिए। शुभेंदु ने कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है।

हावड़ा की पार्वती दास फिर सुर्खियों में

103 साल की उम्र में भरा एसआईआर फार्म

पार्वती दास का जन्म 12 अगस्त 1923 को हुआ

राज्य की सबसे बुजुर्ग मतदाताओं में शामिल हैं

बीएलओ ने घर जाकर किया सम्मानित

निज संवाददाता : हावड़ा के रामराजतला मोड़ के पास रहने वाली 103 साल की पार्वती दास एक बार फिर सुर्खियों में हैं। शिवपुर विधानसभा क्षेत्र की इस बुजुर्ग मतदाता का इस बार भी एन्यूमरेशन फॉर्म भरा गया और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। उनके उत्साह और देश के प्रति जिम्मेदारी को देखते हुए बीएलओ और बीएलए ने उनके घर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। गौरतलब है कि पार्वती दास का जन्म 12 अगस्त 1923 को हुआ था और वह राज्य की सबसे बुजुर्ग मतदाताओं में शामिल हैं। 2002 से लेकर अब तक हर चुनाव में उनका नाम मतदाता सूची में मौजूद है। कई साल पहले उनके पति का निधन हो चुका है। वह अपने बेटे, बहू और अन्य रिश्तेदारों के साथ रहती हैं। उम्र अधिक होने

के कारण चलने-फिरने में परेशानी होती है और आंखें भी कमजोर हो चुकी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने घर पर ही वोट डाला था। शिवपुर विधानसभा क्षेत्र के 227 नंबर पार्ट में उनका नाम शामिल है। राज्य में इन दिनों चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसी क्रम में बीएलओ उनके घर एन्यूमरेशन फॉर्म लेकर पहुंचे थे। परिवार ने फॉर्म को भरकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करा दिया। बीएलओ रूपा लाहिड़ी और बीएलए टू अमर दत्ता ने पार्वती दास को उनके घर पर सम्मानित किया। उनके गले में उत्तरिया पहनाया गया और हाथ में गुलाब का फूल दिया गया। सम्मान पाने के बाद पार्वती दास ने कहा-मैंने पहले भी वोट दिया है, और इस बार भी जरूर वोट दूंगी। मैं देश का कल्याण चाहती हूं। उनकी बात सुनकर वहां मौजूद अधिकारी भी भावुक हो गए। बीएलओ ने कहा कि पार्वती दास राज्य की सबसे बुजुर्ग मतदाता हैं और अब भी खुद सोच-समझकर निर्णय लेती हैं। ऐसे लोग जब तक जीवित हैं, देश का उतना ही भला होगा। बीएलए टू अमर दत्ता ने कहा कि इतने बुजुर्ग मतदाता को सम्मान देना गर्व की बात है। उनका एन्यूमरेशन फॉर्म समय पर भरकर अपलोड कर दिया गया है।

कोलकाता अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला-2026 की तैयारियां जोरों पर

■अर्जेंटीना रहेगा थीम देश ■22 जनवरी से 3 फरवरी तक चलेगा मेला

निज संवाददाता : कोलकाता अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला, एशिया के सबसे बड़े साहित्यिक आयोजनों में से एक, हर वर्ष लाखों पुस्तकप्रेमियों को आकर्षित करता है। 1976 में शुरू हुआ यह मेला न केवल पुस्तकों की विविध दुनिया को सामने लाता है, बल्कि समृद्ध सांस्कृतिक गतिविधियों, साहित्यिक चर्चाओं, पुस्तक विमोचन और विभिन्न प्रदर्शनियों के माध्यम से सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी प्रोत्साहित करता है। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए 49वां अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 22 जनवरी से 3 फरवरी 2026 तक करुणामयी, साल्टलेक के सेंट्रल पार्क ('बोइमेला प्रांगण') में आयोजित होगा। पुस्तक मेला की आयोजक संस्था पब्लिशर्स एंड बुकसेलर्स गिल्ड ने हाल ही में इसकी औपचारिक घोषणा की। इस बार का थीम देश अर्जेंटीना रहेगा, जो पहली बार पुस्तक मेले में भाग ले रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मेले का उद्घाटन करेंगी। समारोह में कई प्रतिष्ठित लेखक, कलाकार, विद्वान और कवि उपस्थित रहेंगे। गिल्ड के

अनुसार-कोलकाता अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला वर्तमान में दुनिया का सबसे अधिक भीड़ वाला नॉन-ट्रेड बुक फेस्टिवल है। वर्ष 2025 के मेले में 27 लाख से अधिक पाठक आए थे और कुल बिक्री 23 करोड़ रुपये तक पहुंची थी। पिछले दिनों गिल्ड की तरफ से थीम देश अर्जेंटीना का आधिकारिक लोगो भी जारी किया गया। अर्जेंटीना के भारत स्थित दूतावास से आंद्रेस सेबास्टियन रोज़ास, राजनीतिक और सांस्कृतिक अनुभाग के प्रमुख, तथा आनंदी कुएपो रियाविट्ज़, कांसुलर सेक्शन की प्रमुख इस अवसर पर उपस्थित थे। गिल्ड ने कहा-हमें विश्वास है कि अर्जेंटीना की सहभागिता भारत और अर्जेंटीना के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करेगी। मेले में ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्पेन, पेरू, कोलंबिया, जापान, थाईलैंड सहित कई लैटिन अमेरिकी देशों के प्रकाशक भाग लेंगे। साथ ही देश के विभिन्न राज्योंदिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, असम, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, त्रिपुरा आदिकी प्रकाशन संस्थाएं भी मौजूद रहेंगी। वर्ष 2027 में कोलकाता अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले की स्वर्ण जयंती मनाई जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए गिल्ड ने 1976 से 1996 के बीच मेले के पहले 20 वर्षों की दुर्लभ और ऐतिहासिक तस्वीरें आमंत्रित की हैं। चयनित 10 सर्वश्रेष्ठ तस्वीरों को सम्मानित किया जाएगा और उन्हें 2026 के प्रेस कॉर्नर में प्रदर्शित किया जाएगा। ये तस्वीरें मेले की 50 वर्ष की स्मारिका में भी प्रकाशित की जाएंगी।

क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रखी जाएगी खास निगरानी

निज संवाददाता : सर्दियों के त्योहारों के मौसम में क्रिसमस और अंग्रेजी नए वर्ष के आस-पास महानगर कोलकाता के होटलों, नाइट क्लबों, रेस्टोरेंट और बार में तैयारियां शुरू हो गई हैं। हर साल इस समय तरह-तरह के कॉन्सर्ट, डीजे नाइट, कल्चरल प्रोग्राम और पार्टियां होती हैं। इसी वजह से कोलकाता नगर निगम दिसंबर के आखिरी हफ्ते में पूरे शहर में खास निगरानी रखने जा रहा है। नगर निगम की एक खास टीम 23 दिसंबर से रात में ऑपरेशन शुरू करेगी ताकि यह पक्का किया जा सके कि एंटरटेनमेंट टैक्स के नियमों का पालन हो रहा है। यह निगरानी 3 जनवरी तक जारी रहेगी। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया-अगर कोई इवेंट बिना परमिशन के होता है, या परमिट की शर्तों को तोड़ा जाता है और कार्यक्रम बहुत ज़्यादा ऑर्गनाइज़ किया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। खासकर अगर कार्यक्रम आधी रात तक होता है, तो टैक्स दोगुना हो जाएगा। टीम हर दिन शाम 6 बजे से सड़कों पर होगी ताकि यह चेक किया जा सके कि इन सभी नियमों का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं। कुछ दिनों में आधी रात के बाद भी रेड की जाएगी। पता चला है कि सिर्फ़ होटल और रेस्टोरेंट ही नहीं, बल्कि शहर के अलग-अलग एग्ज़िबिशन, मेला ग्राउंड, पार्क या खुले मैदानों में होने वाले इवेंट भी इस सर्विलांस के दायरे में आएंगे। नगर निगम के सूत्रों का दावा है कि कुछ मामलों में, मेले या एग्ज़िबिशन के नाम पर बड़े एंटरटेनमेंट इवेंट आयोजित करने के बावजूद टैक्स नहीं दिया जाता है। अगर इस साल ऐसी कोई चोरी पकड़ी जाती है तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। कोलकाता में त्योहारों का मौसम हमेशा व्यस्त रहता है। क्रिसमस और नए साल की शाम को पार्क स्ट्रीट से लेकर साल्टलेक तक, गरियाहाट से लेकर न्यूटाउन तक-हर इलाका एंटरटेनमेंट का सेंटर बन जाता है।

बिना किसी सरकारी सहायता के स्थानीय लोगों ने दार्जिलिंग में बनाया 140 फीट लंबा पुल

नाम रखा 'गोरखालैंड'

निज संवाददाता : दार्जिलिंग में स्थानीय लोगों ने बिना किसी सरकारी सहायता के लगभग 140 फीट लंबे एक पुल का निर्माण किया। बीते 7 दिसंबर को इस पुल का उद्घाटन किया गया। पुल के निर्माण के लिए स्थानीय लोगों ने योगदान किया। सबने अपनी क्षमता के अनुसार रुपये दिए और फिर ब्रिज बनाया गया। इस पुल का नाम गोरखालैंड रखा गया है। गौरतलब है कि बंगाल के मैदानी इलाकों में अलग गोरखालैंड की मांग से जुड़ी प्रबल भावनाओं को देखते हुए, इसकी प्रतीकात्मकता पहाड़ों से परे भी गूंजने की संभावना है। बालासन नदी पर बने इस पुल का निर्माण सरकार ने नहीं, बल्कि श्रमिक दान (ग्रामीणों के स्वैच्छिक श्रमदान) और भारतीय गोरखा जनशक्ति मोर्चा (आईजीजेएफ) के मुख्य संयोजक अजय एडवर्ड्स ने किया है। अजय एडवर्ड्स ने इसके निर्माण के लिए सीमेंट और छड़ें उपलब्ध कराई थीं। यह परियोजना जनवरी 2025 में शुरू हुई और स्थानीय समुदायों की भागीदारी से लगभग एक साल में पूरी हुई। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, पुल का नाम और इसके निर्माण की परिस्थितियां बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले पहाड़ियों को प्रभावित कर सकती हैं। गोरखालैंड की मांग आज भी दार्जिलिंग की राजनीति के पीछे एक मार्गदर्शक शक्ति है। 2017 के गोरखालैंड आंदोलन के बाद से पहाड़ के किसी भी महत्वपूर्ण राजनीतिक

दल द्वारा इस मुद्दे को नहीं उठाए जाने के कारण, यह मांग हाल ही में धीमी पड़ गई है। एक राजनीतिक विशेषज्ञ ने कहा कि इस संदर्भ में, एडवर्ड्स द्वारा पुल का नाम गोरखालैंड रखने और उस पर एक विशाल (60 फीट से अधिक ऊंची) नाम पट्टिका लगाने का निर्णय पहाड़ के कई लोगों को रास नहीं आ रहा है। एडवर्ड्स की आईजीजेएफ गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) में मुख्य विपक्षी दल है। जीटीए का संचालन अनित थापा के नेतृत्व वाली भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा (बीजीपीएम) करती है, जो पहाड़ में तृणमूल कांग्रेस का सहयोगी है। थापा ने कभी भी गोरखालैंड की मांग का विरोध नहीं किया है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस बंगाल के किसी भी और विभाजन के स्पष्ट रूप से खिलाफ है। भारतीय गोरखा जनशक्ति मोर्चा (आईजीजेएफ) के प्रमुख अजय एडवर्ड्स ने रविवार को इस पुल का उद्घाटन किया। यह पुल 16 स्थानीय समाज ने मिलकर बिना किसी सरकारी सहायता के बनाया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह पुल उन लोगों की इच्छाशक्ति का प्रतीक है, जिन्होंने एडवर्ड्स फाउंडेशन और आईजीजेएफ की मदद और समर्थन से पुल के निर्माण किया। एडवर्ड्स ने गोरखालैंड आंदोलन में बलिदानों पर प्रकाश डाला और इसे गोरखा पहचान की धड़कन बताया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना जनशक्ति का प्रमाण है। अगर एकजुट हों, तो गोरखा कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में कई बार तोड़फोड़ की कोशिशें हुईं, जिनमें पुलिस की धमकियां, आपूर्ति में रुकावटें और सूरज तमांग जैसे समन्वयकों का उत्पीड़न शामिल है। हर तरह के दबाव के बावजूद, निवासियों ने स्वैच्छिक श्रम के माध्यम से इसे पूरा किया, और गोरखालैंड क्षेत्रीय प्राधिकरण (जीटीए) और पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोधों को अनसुना किए जाने के बाद एडवर्ड्स ने सामग्री की आपूर्ति की। एडवर्ड्स ने कहा कि सरकार को इस क्षेत्र की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दार्जिलिंग शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित यह पुल, टूंगसूंग (एक बंद चाय बागान) को पोखरियाबोंग से जोड़ता है। आईजीजेएफ ने दावा किया कि कुल 29 स्थानीय समाजों (सामुदायिक संगठनों) ने प्रशासन से की गई उनकी अपील अनसुनी होने के बाद एडवर्ड्स से हस्तक्षेप की अपील की थी। 16 फ़रवरी, 2017 को जारी बंगाल सरकार की एक अधिसूचना में पुलों या पुलियों का निर्माण करने वाली सरकारी एजेंसियों के अलावा अन्य संस्थाओं के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे। एक सूत्र ने कहा कि निर्माण से पहले अनुमति के लिए व्यक्तियों को सिंचाई और जलमार्ग विभाग के वेब पोर्टल www.wbiwd.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि सरकारी मंज़ूरी न मिलने के बावजूद, पुल का निर्माण पूरा हो गया। इसका उद्घाटन मुख्यतः राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण हुआ, क्योंकि पहाड़ों में कोई भी राज्य के दर्जे की भावना का विरोध नहीं कर सकता।

कोलकाता नगर निगम ने उठाया अनूठा कदम

अब अंडरग्राउंड होगी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग

निज संवाददाता: अभी तक मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग की छतों पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की जाती रही है। अब यह अंडरग्राउंड होगा। कोलकाता नगर निगम (केएमसी) एक अनूठा कदम उठा रहा है। शहर के 144 वार्ड में से करीब 90 इलाकों की पहचान की गई है। जहां मॉनसून में पानी बह जाता है। पंपिंग करके पानी निकालना पड़ता है। उन जगहों पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की जाएगी। खबर है कि म्युनिसिपल ड्रेनेज डिपार्टमेंट ने सर्वे पहले ही पूरा कर लिया है। कोलकाता नगर निगम के सूत्रों के मुताबिक, कोलकाता नगर निगम ईस्ट इंडिया में यह प्रोजेक्ट करने वाली पहली म्युनिसिपैलिटी है। बारिश का पानी जमीन से 10 मीटर नीचे दो अलग-अलग चैंबर में इकट्ठा करके फिल्टर किया जाएगा, और फिर नेचर में वापस कर दिया जाएगा। इससे कोलकाता को दो तरह से फायदा होगा। पहला, निचले इलाकों में बारिश के पानी को कुछ हद तक मैनेज किया जा सकेगा। दूसरी और बहुत ज़रूरी बात यह है कि सदियों से कोलकाता के बड़े इलाकों में गहरे ट्यूबवेल से पानी निकाला जाता था। अब भी, आस-पास के इलाकों के कुछ वार्ड पंप के पानी पर डिपेंडेंट हैं। इस वजह से, मिट्टी का ग्राउंडवॉटर लेवल कम होने लगा

है। विशेषज्ञों ने कई बार आर्सेनिक फैलने की चिंता भी जताई है। रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की वजह से अगर बारिश का पानी मिट्टी में मिल जाए, तो वह समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। पानी का लेवल धीरे-धीरे बढ़ेगा। नगर निगम के एक अधिकारी के मुताबिक, ज़मीन के ऊपर एक खुला पाइप होगा। उस पाइप के ज़रिए बारिश का पानी ज़मीन से कम से कम 10 मीटर नीचे 7 फ़ीट लंबे और 4.5 फ़ीट चौड़े चैंबर में जमा किया जाएगा। जब बिना ट्रीट किया हुआ पानी जम जाएगा, तो उसे बगल में बने माइक्रो चैंबर में भेजा जाएगा। दूसरे स्टेज में फ़िल्टर होने के बाद पानी ज़मीन में मिल जाएगा। गार्डन रीच वॉटर प्रोडक्शन और सप्लाई सेंटर के अंदर इस प्रोजेक्ट के लिए जगहों की पहचान करने का काम शुरू हो गया है, जिसमें उत्तर कोलकाता में बाग़बाज़ार या अमहर्स्ट स्ट्रीट या साउथ कोलकाता में बालीगंज आउटपोस्ट, चेतला, कालीघाट, जज कोर्ट रोड शामिल हैं। नगर निगम के सूत्रों के मुताबिक, काम को आसानी से पूरा करने के लिए संबंधित नगर चेयरमैन से सलाह-मशविरा करके काम किया जाएगा। क्योंकि, नगर चेयरमैन ही बता पाएंगे कि किस इलाके में पानी जमा हो रहा है। असल में, बारिश के पानी को साफ़ करके ज़मीन में वापस भेजने के इस प्रोजेक्ट को लेकर नगर निगम के अधिकारी बहुत उत्साहित हैं। क्योंकि अगर यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो राज्य की दूसरी नगर पालिकाओं में भी इस तरह से बारिश के पानी को ज़मीन में वापस भेजने का काम शुरू हो जाएगा।

हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद चाल से ममता बनर्जी की सत्ता पर मंडराया संकट

दिवाकर पाण्डे

पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों हलचल मची हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो 15 साल से सत्ता की कमान संभाल रही हैं, अब चारों तरफ से घिरी नजर आ रही हैं। एक तरफ हिंदू वोटरों का झुकाव भाजपा की ओर हो चुका है, तो दूसरी तरफ उनकी मुस्लिम तुष्टिकरण की पुरानी राजनीति भी डगमगा रही है। ताजा संकट खड़ा कर दिया है उनकी ही पार्टी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने। बीते 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति बनाने की नींव रखने का ऐलान कर उन्होंने न सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया, बल्कि पूरे राज्य की सांप्रदायिक सियासत को नई हवा भी दे दी। यह घटना महज एक विधायक का विद्रोह नहीं, बल्कि ममता की सत्ता की नींव हिला देने वाली चाल लग रही है। हुमायूं कबीर कौन हैं, यह जानना जरूरी है। मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से 2021 में तृणमूल के टिकट पर विधायक बने कबीर पहले भी विवादों के केंद्र में रहे हैं। ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके वे मूल रूप से कांग्रेसी पृष्ठभूमि के हैं। 2011 में ममता के सत्ता में आने पर वे मंत्री बने, लेकिन 2015 में पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने ममता पर आरोप लगाया कि वे अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को राजा बनाने की कोशिश कर रही हैं। नतीजा यह हुआ कि उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। 2021 में वनवास खत्म हुआ और तृणमूल ने फिर मौका दिया। लेकिन अब फिर वही पुरानी कहानी। लोकसभा चुनाव के दौरान कबीर ने कहा था कि मुर्शिदाबाद में 70 फीसद मुस्लिम आबादी है, इसलिए हिंदुओं को भागीरथी नदी में डुबो देंगे। यह बयान सुर्खियां बटोर गया। अब बाबरी मस्जिद का राग छेड़कर वे ममता को सीधा चुनौती दे रहे हैं। 6 दिसंबर का दिन खास था।

बाबरी विध्वंस की 32वीं बरसी पर कबीर ने बेलडांगा में शिलान्यास किया। कार्यक्रम में तीन लाख लोग जुटे, 40 हजार बिरयानी के पैकेट बंटे और सऊदी से आए धर्मगुरुओं ने आशीर्वाद दिया। मंच से कबीर ने कहा कि तीन साल में मस्जिद बनकर तैयार हो जाएगी। उन्होंने 25 नवंबर को ही ऐलान किया था कि 6 दिसंबर को नींव रखेंगे। तृणमूल ने इसे सांप्रदायिक राजनीति बताकर उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। ममता ने कबीर को आरएसएस का मुखौटा करार दिया। पार्टी का कहना है कि निलंबन बाबरी मुद्दे के लिए नहीं, बल्कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए हुआ। लेकिन कबीर पीछे हटने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि ममता मेरी हत्या भी करवा सकती हैं, लेकिन मस्जिद बनेगी। वे नई पार्टी बनाने और 90 मुस्लिम बहुल सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके हैं। यह सब ममता के लिए कितना बड़ा झटका है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 30 फीसद है। 2011 की जनगणना के मुताबिक 27 फीसद थी, जो अब बढ़कर 30 के आसपास पहुंच गई। मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे सीमावर्ती जिलों में

ममता का मुस्लिम तुष्टिकरण अब उल्टा पड़ रहा है। वक्फ संशोधन कानून पर उनका यू-टर्न इसका बड़ा उदाहरण है। अप्रैल 2025 में ममता ने कहा था कि बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने दूंगी। तृणमूल ने सड़क से संसद तक हंगामा किया। मुस्लिम समुदाय खुश था। लेकिन बाद में उन्होंने पोर्टल पर वक्फ संपत्ति का ब्योरा अपलोड करने की इजाजत दे दी। इससे मुस्लिमों में गुस्सा भड़का। उन्हें लगने लगा कि ममता भी भाजपा जैसी हो गई हैं।

बांग्लादेशी घुसपैठियों की भरमार है। कबीर का दावा है कि 90 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट 35 फीसद से ज्यादा हैं। ममता ने हमेशा अल्पसंख्यक वोटों को सहारा बनाया। इमामों को तनख्वाह, धार्मिक जुलूसों का समर्थन सब कुछ किया। लेकिन अब कबीर की चाल से वोट बंटवारे का खतरा मंडरा रहा। भाजपा को इसका फायदा होगा, जो हिंदुत्व कार्ड खेल रही है। वीएचपी ने चेतावनी दी कि अगर बाबरी बहाने से हिंदुओं पर हमला हुआ तो कबीर और ममता जिम्मेदार होंगे। हाईकोर्ट ने भी दखल देने से इनकार कर दिया, जिससे कबीर को हौसला मिला। ममता का मुस्लिम तुष्टिकरण अब उल्टा पड़ रहा है। वक्फ संशोधन कानून पर उनका यू-टर्न इसका बड़ा उदाहरण है। अप्रैल 2025 में ममता ने कहा था कि बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने दूंगी। तृणमूल ने सड़क से संसद तक हंगामा किया। मुस्लिम समुदाय खुश था। लेकिन बाद में उन्होंने पोर्टल पर वक्फ संपत्ति का ब्योरा अपलोड करने की इजाजत दे दी। इससे मुस्लिमों में गुस्सा भड़का। उन्हें लगने लगा कि ममता भी भाजपा जैसी हो गई हैं। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव की तरह वादा किया, लेकिन महागठबंधन की हार देखकर रुख बदला। मुर्शिदाबाद में वक्फ विरोधी हिंसा हुई, जिसमें भाजपा ने ममता पर बांग्लादेश बनाने का आरोप लगाया। मौलाना साजिद रशीदी जैसे नेताओं ने राष्ट्रपति शासन की मांग की। दूसरा बड़ा संकट है विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची साफ करने के लिए 'एसआईआर' शुरू किया। ममता ने इसे अमित शाह की साजिश बताया। कहा कि अगर रोकतीं तो केंद्र राष्ट्रपति शासन लगा देता। एसआईआर से 46 लाख नाम कट सकते हैं, जिनमें ज्यादातर घुसपैठिए। ममता ने विरोध में रैलियां की। मालदा में कहा कि भाजपा अपनी कब्र खोद रही है। एसआईआर से 40 मौतें हुईं, जिनमें आधे हिंदू। ममता ने मुआवजा देने की घोषणा की और निगरानी टीम बनाई। लेकिन आयोग ने उनकी बाधा को नकार दिया। सीमावर्ती जिलों में वोटरों की संख्या दोगुनी हो गई, जो भाजपा घुसपैठ का सबूत बता रही। बंगाल में एक करोड़ फर्जी वोटर होने का दावा कर रही। मुस्लिम बहुल इलाकों में 'एसआईआर' फॉर्म भरने की होड़ लगी, लेकिन ममता का विरोध जारी है। वे घुसपैठियों को सांत्वना दे रही हैं कि डरें नहीं, वापस बुलाएंगी। 20 साल पहले लोकसभा में घुसपैठ पर बवाल काटने वाली ममता अब उलट बोल रही हैं। भाजपा इन सबका फायदा उठाने को बेताब है। 2021 में 77 विधायक जीतकर राज्य में मजबूत हुई। अब हिंदू वोट उसके पाले में हैं। वंदे मातरम विवाद से बंगाली अस्मिता जोड़ रही। मुस्लिम आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया, ताकि बंगाली मुसलमानों को साधे। ओबीसी लिस्ट से 35 मुस्लिम जातियों को हटाने पर तृणमूल-भाजपा भिड़ गई। जाति सर्वे को भेदभाव बढ़ाने वाला बता रही। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी बंगाल में दखल दे रही, जिस पर भाजपा की मदद का आरोप है। कबीर का बीजेपी से पुराना रिश्ता रहा। 2019 में वे भाजपा से लड़े। अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने उन्हें मानसिक रूप से बीमार और भाजपा एजेंट कहा। 2026 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ममता की स्थिति सांप-छछूंदर जैसी हो गई। न निगलते बन रहा, न उगलते। हुमायूं कबीर का खेल कामयाब हुआ तो तृणमूल का वोट बैंक बंट जाएगा। मुस्लिम वोट भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे। बंगाल की सियासत में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेज हो रहा। ममता को बड़ा सबक मिल सकता है। क्या वे अपनी सेकुलर छवि बचा पाएंगी? या भाजपा सत्ता की चाबी हाथ में ले लेगी? समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल हुमायूं कबीर की बाबरी चाल ने सबको चौंका दिया है। बंगाल की सड़कों पर बहस छिड़ गई है क्या यह ममता का अंतिम संकट है?

हल करो हीरो बनो का उत्तर

1.बाराबंकी 2.खुर्जा, 3.प्रिया कुशवाहा, 4.विश्वंम्बर दयाल, 5.जौनपुर, 6.आंध्र प्रदेश

संपादकीय

संसद में ''वंदे मातरम'' पर चर्चा से उठते कई गंभीर सवाल

कभी-कभी एक गाने की ज़िंदगी, एक लोकतंत्र की ज़िंदगी में होने वाले बदलावों को दिखाती है। भारत के राष्ट्रीय गीत ''वंदे मातरम'' के 150 साल पूरे होने पर संसद में चर्चा हुई। यह चर्चा इन बदलावों का सबूत थी, जो ज़रूरी नहीं कि सुकून देने वाले हों। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की शुरुआत में जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों को खुश करने के काम में शामिल होने का आरोप लगाया इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है जिसकी वजह से गाने से कुछ लाइनें हटा दी गईं। विपक्ष का यह जवाब कि पीएम मोदी तथ्यों के साथ कंजूसी कर रहे हैं, खारिज नहीं किया जा सकता। ऐतिहासिक तथ्यों को बिना किसी भेदभाव के देखने पर पता चलता है कि रवींद्रनाथ टैगोर की ''वंदे मातरम'' के पहले दो लाइनों को अपनाने की सलाह, ताकि इसे अलग-अलग तरह की भावनाओं से छुटकारा मिल सके, न सिर्फ कांग्रेस वर्किंग कमेटी बल्कि संविधान सभा के सदस्यों, जिनमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे, ने भी इसे माना था। इतिहास प्रधान मंत्री की ताकत नहीं है; राजनीतिक फायदे के लिए इसे तोड़-मरोड़कर पेश करना है। और इतिहास खुद को दुखद घटना के तौर पर दोहराता है, यह इस बात से पता चलता है कि जिस गाने ने एक सताए गए देश और उसके लोगों को देश की आज़ादी के लिए लड़ते हुए एकजुट किया, उसे आज़ादी के दशकों बाद, बांटने का ज़रिया बनाया जा रहा है।सिर्फ़ इतिहास ही नहीं, बल्कि ''वंदे मातरम'' से कुछ लाइनों को हटाने के मामले में तुष्टिकरण के आरोप का भी नैतिक आधार पर कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए। भारत का आज़ादी का आंदोलन और उसके बाद गणतंत्र के बुनियादी नज़रिए को आकार देना, प्लूरलिज़्म के स्वागत योग्य सिद्धांत पर आधारित था। भले ही धार्मिक समावेश भारत के उपनिवेशवाद-विरोधी विद्रोह का आधार था, लेकिन धार्मिक आधार पर देश के बंटवारे के रूप में इसकी सबसे बड़ी नाकामी हुई। आज़ादी के बाद बहुलवाद के प्रति गणतंत्र की प्रतिबद्धता को एक नए सामूहिक वादे के तौर पर पढ़ा जाना चाहिए कि वह फिरकापरस्ती के जाल में न फंसे। आज़ादी के तीन साल बाद राष्ट्रीय गीत के तौर पर ''वंदे मातरम'' को उसके छोटे रूप में पूरी दुनिया में मंज़ूरी मिलने को इसी संदर्भ में देखने की ज़रूरत है। दुख की बात है कि नए भारत और इसके बनाने वालों को रिपब्लिक का मेजॉरिटी वाला रुख पसंद आ रहा है। ऐसे समय में जब आधुनिक भारत और संसद को ज़रूरी मामलों पर ध्यान देना है, इस विषय पर उनका विवाद खड़ा करना गलत है।

मसूरी में 600 प्रशिक्षु आईएएस और एक सवाल

उंगलियों पर हल होने वाला सवाल और भविष्य के प्रशासकों की तैयारी का सच

डॉ. प्रियंका सौरभ

उत्तराखंड के शांत, अनुशासित और सुसंस्कृत वातावरण में स्थित मसूरी का प्रसिद्ध प्रशासनिक अकादमी परिसरलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमीदेश के सर्वोच्च सिविल सेवकों के निर्माण का केंद्र बिंदु है। यहां आज भी 600 से अधिक प्रशिक्षु अधिकारी भविष्य के भारतीय प्रशासन की रूपरेखा तय करने की तैयारी में डटे हैं। हाल ही में 100वें फाउंडेशन कोर्स का समापन समारोह आयोजित किया गया, जो किसी भी संस्थान के लिए गौरव का क्षण होता है। इस अवसर पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा और भी बढ़ा दी।

मसूरी में घटित यह छोटा-सा घटना क्रम इस बात का प्रतीक है कि नेतृत्व की ताकत केवल बड़े भाषणों या उच्च ज्ञान में नहीं, बल्कि सरल तर्क और मौलिक समझ में भी निहित होती है। सिविल सेवा के भविष्य को आकार देने वाले प्रशिक्षुओं के लिए यह एक स्मरणीय संदेश है प्रशासन की महानता सरलता में है, न कि जटिलता में।

समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने एक सरल-सा गणितीय प्रश्न पूछा एक आदमी के पास कुछ पैसे थे। उसने आधा ए को, एक-तिहाई बी को और शेष 100 रुपये सी को दिए। बताइए, कुल पैसा कितना था? दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाला यह सीधा-सा सवाल प्रशिक्षुओं के लिए अप्रत्याशित सिद्ध हुआ। कई प्रशिक्षु अधिकारी प्रश्न में उलझ गए, जबकि समाधान उंगलियों पर किया जा सकता था। बाद में स्वयं राजनाथ सिंह ने इसे सरल तरीके से हल कर समझाया। यह घटना भले ही साधारण प्रतीत हो, पर प्रशासनिक प्रशिक्षण और नेतृत्व क्षमता की वास्तविक दिशा पर यह बेहद महत्त्वपूर्ण संकेत देती है। प्रशासनिक कार्यों का मूल तत्व केवल कानून और नियमों का ज्ञान नहीं, बल्कि तुरंत समझने, तर्क लागू करने और व्यवहारिक समाधान निकालने की क्षमता है। कभी-कभी सबसे कठिन परिस्थितियों में सर्वाधिक सरल समाधान ही सर्वश्रेष्ठ होता हैपर इसके लिए मन का खुलापन और व्यावहारिक सोच आवश्यक होती है। यही गुण एक सक्षम प्रशासक को भीड़ से अलग करता है।

यह घटना इस बात का स्मरण भी कराती है कि सिविल सेवा केवल अकादमिक बौद्धिकता का अभ्यास नहीं है; यह मानव स्वभाव, सामाजिक व्यवहार, त्वरित निर्णय-क्षमता और सामान्य समझ की मांग भी करती है। किसी भी शासन प्रणाली में सबसे प्रभावशाली अधिकारी वही होता है जो जटिल समस्याओं को सरलता से हल करने की क्षमता रखता हो। प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन नहीं, बल्कि व्यवहारिक बुद्धि का विकास भी है। एक छोटा सा प्रश्न प्रशिक्षुओं को यह याद दिलाता है कि वास्तविक प्रशासन वही है जो खेत-खलिहान, बाज़ार, थाने, पंचायत भवन और कार्यालयों में घटित होता है जहां जटिलताएं कम और सादगी अधिक काम आती है। राजनाथ सिंह द्वारा पूछा गया प्रश्न प्रशासनिक सोच के दो महत्त्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करता है। पहला, अधिकारी का ध्यान समस्या के मूल की ओर होना चाहिए, न कि उसकी सतही जटिलता की ओर। दूसरा, किसी भी चुनौती में घबराना नहीं, बल्कि उसे विभाजित कर सरल रूप में हल करना चाहिए। सिविल सेवाओं में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब अधिकारी को अचानक लिए गए निर्णयों के आधार पर जनता को राहत, दिशा और सुरक्षा प्रदान करनी होती है। यदि वह क्षणिक दबाव में भी सामान्य तर्क बनाए रखने में दक्ष है, तो वह बेहतर प्रशासक बन सकता है।

यह प्रसंग इस व्यापक प्रश्न को भी जन्म देता है कि आधुनिक प्रशिक्षण पद्धति कहीं अत्यधिक तकनीकी, सैद्धांतिक या औपचारिक तो नहीं हो गई है? क्या हम प्रशासन के मूल तत्वसरलता, संवेदनशीलता और सामान्य विवेकको नजरअंदाज तो नहीं कर रहे?

सिविल सेवा का इतिहास बताता है कि देश के श्रेष्ठ अधिकारी वही रहे, जिन्होंने अत्यधिक बुद्धि के साथ-साथ सरल सोच,जन-संपर्क की क्षमता और सहज निर्णय-प्रक्रिया अपनाई। आज जब देश नई चुनौतियों प्रौद्योगिकी, जटिल प्रशासनिक व्यवस्था, विस्तृत जनसंख्या और त्वरित परिवर्तनोंसे गुजर रहा है, तब एक प्रशासक की भूमिका और भी विस्तृत और बहुआयामी हो चुकी है। ऐसे समय में यह आवश्यक है कि प्रशिक्षण केवल परीक्षाओं और पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न हो। उसमें व्यवहारिक गणित, तर्कशक्ति, सामान्य समझ, मनोवैज्ञानिक संतुलन और परिस्थितिजन्य विश्लेषण को भी समुचित स्थान मिले। राजनाथ सिंह द्वारा हल्का-सा पूछा गया यह प्रश्न प्रशासनिक तंत्र को यह संदेश देता है कि नेतृत्व की असल परीक्षा कभी-कभी छोटे-छोटे क्षणों में ही होती है। बड़े निर्णयों का आधार भी वही अधिकारी बनता है जो बेसिक समझ को खोने नहीं देता। इस प्रसंग से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रशिक्षण के दौरान आने वाले ऐसे अप्रत्याशित प्रश्न अधिकारी के मन को गति देते हैं, उसे दबाव में सोचने की क्षमता प्रदान करते हैं और वास्तविक प्रशासनिक दुनिया के लिए मानसिक रूप से तैयार करते हैं। समय के साथ यह आवश्यक हो गया है कि सिविल सेवा प्रशिक्षण अकादमियां इस प्रकार के संवाद, प्रश्न-आधारित परीक्षण और व्यवहारिक अभ्यास को और भी अधिक बढ़ाएं। इससे अधिकारी न केवल जनसेवा के लिए अधिक तैयार होंगे बल्कि प्रशासनिक जटिलताओं को सहजता से हल करने की क्षमता भी विकसित करेंगे।

निष्कर्षतः मसूरी में घटित यह छोटा-सा घटना क्रम इस बात का प्रतीक है कि नेतृत्व की ताकत केवल बड़े भाषणों या उच्च ज्ञान में नहीं, बल्कि सरल तर्क और मौलिक समझ में भी निहित होती है। सिविल सेवा के भविष्य को आकार देने वाले प्रशिक्षुओं के लिए यह एक स्मरणीय संदेश है प्रशासन की महानता सरलता में है, न कि जटिलता में।

जानें अपना राशिफल

मेष
धैर्य रखकर काम करने वाला समय हो सकता है, कोई चमत्कारी काम बन सकता है, अपनी आय बढ़ाने का प्रयास करने की आवश्यकता है, अपनी सोच सकारात्मक रखने की जरूरत है।

वृषभ
कर्तव्य करने वाला समय हो सकता है इसलिए ज्यादा से ज्यादा काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोई बड़ा काम करने का अवसर मिल सकता है प्रयास करे, मन में उत्साह रहेगा।

मिथुन
अविश्वास वाला समय हो सकता है इसलिए सिर्फ काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोई परिवार का सदस्य आपका समय खराब कर सकता है सावधान रहे, आपसी प्रेम बनाये रखे।

कर्क
सम्मान बचाने वाला समय हो सकता है इसलिए ज्यादा से ज्यादा काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोई मित्र आपका काम बिगाड़ सकता है सावधान रहे, बिना काम बाहर नहीं जाये।

सिंह
प्रमुख समय हो सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं फायदा अवश्य होगा, किसी पर भरोसा करके काम करने की आवश्यकता है, अपनी सोच सकारात्मक रखने की आवश्यकता है।

कन्या
निवेश करने वाला समय हो सकता है, कोई बड़ा काम करने का अवसर मिल सकता है प्रयास करे, कोई विदेश में कार्य हेतु चर्चा हो सकती है जो सफल रहेगी, जीवनसाथी पुरा साथ दे सकते हैं।

तुला
मनोकामना पूर्ण होने वाला समय हो सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं फायदा अवश्य होगा, अचानक धन लाभ भी हो सकता है, किसी पर भरोसा करके काम करने की आवश्यकता है।

वृश्चिक
उदारता दिखाने वाला समय हो सकता है, किसी परिवार के सदस्य से मतभेद भी हो सकता है सावधान रहे, किसी नये व्यक्ति से काम आगे बढ़ सकता है प्रयास करे, आपसी सहमति बनाये रखे।

धनु
बलशाली समय हो सकता है, कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है प्रयास करे, कोई जमीन का काम भी आगे बढ़ सकता है, अपनी सोच सकारात्मक रखने की आवश्यकता है।

मकर
असंतोष वाला समय हो सकता है इसलिए सिर्फ काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, किसी अन्य व्यक्ति से काम बिगड़ सकता है सावधान रहे, अपनी बुद्धिमानी दिखाने की आवश्यकता है।

कुंभ
क्षमा करने वाला समय हो सकता है, किसी परिवार के सदस्य से मतभेद भी हो सकता है सावधान रहे, किसी पर ज्यादा भरोसा परेशानी का कारण बन सकता है, आपसी सहमति बनाये रखे।

मीन
लालची समय हो सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं सोच समझकर ही करे, किसी के बहकावे में आने से बनता काम बिगड़ सकता है सावधान रहे, अपने परिवार को प्रसन्न रखे।

साधु और ठग

एक बार की बात है, किसी गाँव के मंदिर में देव शर्मा नाम का एक प्रतिष्ठित साधू रहता था। गांव में सभी लोग उनका सम्मान करते थे। उसे अपने भक्तों से दान में तरह- तरह के वस्त्र, उपहार, खाद्य सामग्री और पैसे मिलते थे। उन वस्त्रों को बेचकर साधू ने काफी धन जमा कर लिया था।

साधू कभी किसी पर विश्वास नहीं करता था और हमेशा अपने धन की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता था। वह अपने धन को एक पोटली में रखता था और उसे हमेशा अपने साथ लेकर ही चलता था।

उसी गाँव में एक ठग रहता था। बहुत दिनों से उसकी नजर साधू के धन पर थी। ठग हमेशा साधू का पीछा किया करता था, लेकिन साधू उस गठरी को कभी अपने से अलग नहीं होने देता।

आखिरकार, उस ठग ने एक छात्र का वेश धारण किया और उस साधू के पास गया। उसने साधू से मिन्नत की कि वह उसे अपना शिष्य बना ले क्योंकि वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। साधू तैयार हो गया और इस तरह से वह ठग साधू के साथ ही मंदिर में रहने लगा।

ठग मंदिर की साफ सफाई से लेकर अन्य सभी कार्य भी करता था और ठग ने साधू की खूब सेवा की और जल्दी ही उसका विश्वासपात्र बन गया।एक दिन साधू को पास के गांव में एक अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया गया, साधू ने वह आमंत्रण स्वीकार किया और निश्चित दिन साधू अपने शिष्य के साथ अनुष्ठान में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ी और साधू ने स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। उसने पैसों की गठरी को एक कम्बल के भीतर रखा और उसे नदी के किनारे रख दिया। उसने ठग से सामान की रखवाली करने को कहा और खुद नहाने चला गया। ठग को तो कब से इसी पल का इंतज़ार था। जैसे ही साधू नदी में डुबकी लगाने गया, वह रुपयों की गठरी लेकर चम्पत हो गया।

शिक्षा: किसी अजनबी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर ही उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए।

खटमल और बेचारी जूं

एक राजा के शयनकक्ष में मंदरीसर्पिणी नाम की जूं ने डेरा डाल रखा था। रोज रात को जब राजा जाता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर जा छिपती। संयोग से एक दिन अग्निमुख नाम का एक खटमल भी राजा के शयनकक्ष में आ पहुंचा। जूं ने जब उसे देखा तो वहां से चले जाने को कहा। उसने अपने अधिकार-क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था। लेकिन खटमल भी कम चतुर न था, बोलो, ''देखो, मेहमान से इसी तरह बर्ताव नहीं किया जाता, मैं आज रात तुम्हारा मेहमान हूं।'' जूं अततः खटमल की चिकनी-चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, ''ठीक है, तुम यहां रातभर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे तो नहीं उसका खून चूसने के लिए।'' खटमल बोला, ''लेकिन मैं तुम्हारा मेहमान है, मुझे कुछ तो दोगी खाने के लिए। और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है।'' ''ठीक है।'' जूं बोली, ''तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, उसे पीड़ा का आभास नहीं होना चाहिए।'' ''जैसा तुम कहोगी, बिलकुल वैसा ही होगा।'' कहकर खटमल शयनकक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर राजा वहां आया और बिस्तर पर पड़कर सो गया। उसे देख खटमल सबकुछ भूलकर राजा को काटने लगा, खून चूसने के लिए। ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था, इसलिए वह राजा को जोर-जोर से काटकर उसका खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद उचट गई। उसने क्रोध में भरकर अपने सेवकों से खटमल को ढूंढकर मारने को कहा। यह सुनकर चतुर खटमल तो पंलग के पाए के नीचे छिप गया लेकिन चादर के कोने पर बैठी जूं राजा के सेवकों की नजर में आ गई। उन्होंने उसे पकड़ा और मार डाला।

सीख : हमें अजनबियों की चिकनी-चुपड़ी बातों में आकर उनपर भरोसा नहीं करना चाहिए अपितु उनसे सावधान ही रहना चाहिए।

हल करो हीरो बनो

1. निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है।
(क) गोरखपुर (ख) मैनपुरी
(ग) मुरादाबाद (घ) बाराबंकी
2. चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है।
(क) फिरोजाबाद (ख) गोरखपुर
(ग) खुर्जा (घ) मुरादाबाद
3. उत्तर प्रदेश का 'सर्वश्रेष्ठ विकलांग एथलीट' किसे घोषित किया गया है।
(क) गुरुदेव (ख) प्रिया कुशवाहा
(ग) राकेश कुमार (घ) मानसी जोशी
4. उत्तर प्रदेश का पहला लोकायुक्त 'लोकपाल' कौन था।
(क) विश्वंम्बर दयाल (ख) जस्टिस संजय मिश्रा
(ग) राम नाईक (घ) चंद्रभाल
5. उत्तर प्रदेश के किस जिले में 'लिंगानुपात' सबसे ज्यादा है।
(क) आजमगढ़ (ख) देवरिया
(ग) गोरखपुर (घ) जौनपुर
6. राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है।
(क) राजस्थान (ख) असम
(ग) मणिपुर (घ) आंध्र प्रदेश

(उत्तर इसी अंक में)

माथापच्ची–16

3		4			8			
	2		1				4	5
	7			6	2			3
			3	4		1		
		9		8		5		
		2		1	6			
2			8	5			3	
5	4				9		2	
			7			6		1

नियम : प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक अंक भरे जाने आवश्यक है, इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है। आड़ी एवं खड़ी पंक्ति में एवं 3X3 के वर्ग में अंक की पुनरावृत्ति न हो, पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते। उत्तर अगले अंक में

मार लो मुस्की

टीचर- पक्षियों की नजर तेज होती है या मनुष्यों की?
चिंटू- पक्षियों की...
टीचर- वो कैसे ?
चिंटू- क्योंकि उन्हें मैंने कभी चश्मा लगाए हुए नहीं देखा।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

पुराने गणित के गुरुजी मिल गए, रिटायर हो चुके थे। हाल चाल पूछा, मन प्रसन्न हो गया। चलते समय मैंने उनका मोबाइल नम्बर पूछा।
गुरुजी ने बताया: नौ अरब सत्तासी करोड सत्तानबे लाख छियासी हजार दो सौ एक।
कसम से, दिमाग की सारी बत्तियां खुल गई।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

मास्टर- सबसे पवित्र वस्तु क्या है?
पप्पू - सर मोबाइल...
मास्टर (गुस्से में) - वो कैसे...?
पप्पू - वह बाथरूम, अस्पताल, श्मशान से होकर आने के बाद भी बिना धोये हुए घर, रसोई और मंदिर सब जगह जा सकता है...!!!

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

मास्टर जी - संगठन में शक्ति है का उदाहरण दो...!
पप्पू - सर जेब में एक सिगरेट रखें तो मुड़-तुड़ जाती है पर यदि पूरा पैकेट रखें तो कड़क ही रहती है!
फिर मास्टर जी ने पप्पू को तोड़-मरोड़ के कूटा...

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

एक नए टीचर ने क्लास में पूछा: भारत के एक महान वैज्ञानिक का नाम बताओ ..?
स्टूडेंट : सर, आलिया भट्ट..
टीचर : छड़ी लेकर, यही सीखे हो?
दूसरा: ये तोतला है सर.. आर्यभट्ट बोल रहा है।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

टीचर- बताओ दुर्भाग्य और दुर्दशा में क्या फर्क है?
बच्चा- सर अगर इस स्कूल में आग लग जाए तो स्कूल की हालत खराब हो जाएगी, इसे कहते है ''दुर्दशा''।
और इतनी आग लगने पर भी आप जिंदा बच गए तो ये होगा हमारा ''दुर्भाग्य''।
फिर क्या... छात्र की हुई जोरदार कुटाई।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

पप्पू की हुई मास्टर से लड़ाई,
मास्टर ने की पप्पू की पिटाई
पप्पू का गरम हुआ खून...
गया कब्रिस्तान और मास्टर की, फोटो टांग के लिख दिया 'कमिंग सून'।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

टीचर- इतने दिन कहां थे, स्कूल क्यों नहीं आए?
गोलू- बर्ड फ्लू हो गया था मैम।
टीचर- पर ये तो पक्षियों को होता है इंसानों को नहीं।
गोलू- इंसान समझा ही कहां आपने, रोज तो मुर्गा बना देती हो!

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

मैडम क्लास का ग्रुप फोटो बच्चों को दिखाकर बोली- जब तुम बड़े हो जाओगे तो इस फोटो को देखकर कहोगे, ये रहा राजू जो अमेरिका चला गया, ये रहा रवि जो लंदन चला गया, और ये रहा नन्दू जो यहीं का यही रह गया..
ये बात सुनकर नन्दू बोला- और ये रही हमारी मैडम जिनका देहांत हो गया..

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

पप्पू- बचपन में, मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था तो एक बार स्कूल ट्रिप के दौरान मैं कुतुब मीनार से गिर गया था।
गप्पू - ओ तेरी... अच्छा फिर क्या हुआ? तू मर गया था या बच गया था?
पप्पू- अबे गधे, मुझे क्या पता, बचपन की सारी बातें कहां याद रहती हैं।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

अध्यापक का विवाह होने पर छात्र ने मैसेज भेजा, सर शादी की बहुत-बहुत बधाई..!
हमें उम्मीद है आप घर का गुस्सा स्कूल में नहीं निकालेंगे..!

माथापच्ची 15 का हल

9	6	3	4	7	8	2	5	1
2	1	4	5	3	9	6	8	7
8	5	7	6	2	1	9	3	4
1	3	8	7	9	6	5	4	2
5	7	6	1	4	2	3	9	8
4	9	2	3	8	5	7	1	6
7	8	5	2	1	3	4	6	9
3	2	1	9	6	4	8	7	5
6	4	9	8	5	7	1	2	3

रेलवे में नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा

परीक्षा 'किसी' ने दी और ज्वाइन करने आया 'कोई और'

निज संवाददाता : रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी गैंग ने हजारों की संख्या में युवकों को लूटा है। ठगों ने आसनसोल डीआरएम कार्यालय का भी उपयोग युवकों को ठगने में किया है। जिसका खुलासा अनेकों मामलों में हुआ है। पिछले दिनों आसनसोल डीआरएम ऑफिस में फर्जीवाड़ा का एक नया मामला सामने आया, जहां नौकरी के लिये परीक्षा किसी और ने दी और ज्वाइनिंग करने कोई और आ गया। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के दौरान मामला फंस गया।

जांच के दौरान कागजातों में भी गड़बड़ी पायी गयी। जो युवक नौकरी के लिए जॉइन करने आया था, वह बांका (बिहार) जिला के बेलहर थाना क्षेत्र के बेलहर गांव का निवासी मिथिलेश कुमार है। उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया और ऑफिस अधीक्षक (नियुक्ति) सुमन चंद्रा ने आसनसोल साउथ थाने में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज करायी। उसके आधार पर कांड संख्या 403/25 में बीएनएस की धारा

318(2)/319(2)/336(2)/340 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई। आरोपी को शुक्रवार अदालत में पेश किया गया। जांच अधिकारी ने इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी पाने और उन्हें गिरफ्तार करने का हवाला देकर दस दिनों की पुलिस रिमांड की अपील की। अदालत ने सात दिनों का रिमांड मंजूर किया। पुलिस उपायुक्त (सेंट्रल) ध्रुव दास ने बताया रेलवे में नौकरी के लिए अनेकों तरह से फर्जीवाड़ा होता है। फर्जीवाड़ा का यह भी एक तरीका है, जहां किसी और के बदले कोई और परीक्षा देता है। अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग होने के कारण यह आरोपी पकड़ा गया है। रिमांड अवधि में इससे सारी जानकारी हासिल करने का प्रयास किया जाएगा।

गौरतलब है कि रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम फर्जीवाड़ा का धंधा वर्षों से चल रहा है। मालूम हो कि शिल्पांचल के विभिन्न थानों में इस प्रकार के अनेकों मामले दर्ज हैं और आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अभी भी इन मामलों की जांच कर रही है। इस बीच एक नया मामला सामने आ गया। ओएस (नियुक्ति) श्री चंद्रा ने अपनी शिकायत में बताया कि गुरुवार को -02/2024 के तहत उम्मीदवारों के डॉक्युमेंट्स की सिक्योरिटी और वेरिफिकेशन के दौरान मिथिलेश कुमार नामक एक डुप्लीकेट कैंडिडेट मिला। आधार और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के दौरान वह पकड़ा गया। जांच के दौरान पाया गया कि नौकरी पाने के लिए उसने कागजात भी नकली जमा दिया है।

बदहाली के शिकार रानीगंज में तार बंगला व शिशु बागान बस स्टैंड

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की तत्काल हस्तक्षेप की मांग

निज संवाददाता : पूर्व विधायक सोहराब अली की ओर से ''विधायक इलाका उन्नयन प्रकल्प'' के तहत रानीगंज के तार बंगला और शिशु बागान इलाकों में निर्मित बस स्टैंड अब अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। समय पर उचित रखरखाव नहीं होने के कारण इन दोनों बस स्टैंडों की हालत इतनी दयनीय हो गयी है कि ये यात्रियों के लिए सहूलियत की जगह ''सिरदर्द'' बन चुके हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए, बस स्टैंड पर यात्रियों का रुकना बेहद मुश्किल हो गया है। स्थानीय निवासी विजय कुमार ने अपनी परेशानी साझा करते हुए बताया कि बस स्टैंड की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब बसें स्टैंड के सामने रुकती ही नहीं हैं, बल्कि थोड़ा आगे रुकती हैं क्योंकि यात्री यहां रुकने से कतराते हैं। उन्होंने बस स्टैंड की बदहाली का पूरा ब्योरा देते हुए कहा कि बस स्टैंड की फॉल्स सीलिंग टूट चुकी है। बिजली की सुविधा होते हुए भी लाइटें काम नहीं करती। बस स्टैंड पर लगी कुर्सियां चोरी हो चुकी हैं और जो बची हैं वे भी टूटी-फूटी हालत में हैं। लोहे की लगी

कुर्सियां ईंट पर टिकाए गए है। अगर कोई सावधानी से उसपर नहीं बैठते है,तो हाथ पैर टूट सकती है। यहां साफ-सफाई बिल्कुल नहीं की जाती, जिसके कारण गंदगी का अंबार लगा रहता है। विजय कुमार ने सबसे चिंताजनक पहलू पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रात होते ही ये दोनों बस स्टैंड शराबियों और नशाखोरों का अड्डा बन जाते हैं। लिहाजा इस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं, जिससे यात्री और स्थानीय लोग शाम के बाद यहां असुरक्षित महसूस करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये बस स्टैंड केवल स्थानीय लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि रानीगंज की छवि के लिए भी बुरा बन रहे हैं। जब रानीगंज से बाहर के लोग शहर आते हैं और इन बदहाल बस स्टैंडों को देखते हैं, तो उनके मन में शहर के बारे में एक खराब धारणा बन जाती है। स्थानीय निवासियों ने वर्तमान विधायक तापस बनर्जी सहित प्रशासन के अन्य लोगों से तत्काल इस विषय पर ध्यान देने का अनुरोध किया है। उनकी मांग है कि इन बस स्टैंडों की मरम्मत, लाइटिंग, साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त किया जाए, ताकि जो ढांचा लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया था, वह वास्तव में उनके काम आ सके। इस मामले में प्रशासन की अगली कार्रवाई क्या होती है, यह देखने लायक होगा।

पुलकारों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग और पुलिस अधिकारियों ने गाड़ी मालिकों को दिया नोटिस

सप्ताह के अंदर प्रशासन का निर्देशों का कार्य पालन

आसनसोलः उलूबेरिया में पुलकार की हुई घटना से सबक लेते हुए आसनसोल जिला परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई है। पुलकारो में लगी गाड़ियों को सुरक्षा को लेकर पहले प्रशासन और परिवहन विभाग जागरूकता अभियान चल रहा था। लेकिन अब प्रशासन और परिवहन विभाग परिवहन विभाग के निर्देश के पालन करने के लिए सख्त हो गया है। गुरुवार को इस अभियान के तहत एडीसीपी के तरफ से डीएवी मॉडल स्कूल में जागरूकता अभियान के तहत एक कार्यक्रम किया गया। जिसमें आसनसोल जिला परिवहन विभाग के मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर और आसनसोल दुर्गापुर कमिश्नर ऑफ पुलिस के अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में स्कूल प्रशासन के सदस्य, प्रिंसिपल मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के अधिकारी,पुलिस प्रशासन का अधिकारी पुलकार के चालक मालिक और छात्रों के अभिभावको ने भाग लिया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन के तरफ से यह कहा गया कि यह अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि अभिभावक और पुलकार के मालिक एवं चालक भी सतर्क हो जाए। ताकि कोई बड़ी दुर्घटना घटने के पहले उसको रोका जा सके। इसलिए यह जरूरी है कि वाहनों का फिटनेस हो, उसकी इंश्योरेंस सही हो, वाहनों में जितनी क्षमता हो उसके अनुसार ही बच्चों को बैठाई जाए। धुंआ परीक्षण की सर्टिफिकेट अप टू डेट हो।

इन सभी बातों पर वाहन मालिकों और चालकों को अनिवार्य रूप से ध्यान देने की बात कही गई। साथ ही इस दौरान ऐसे वाहनों पाय गए जिनकी 2 सालों से अधिक फिटनेस, इंश्योरेंस, धुआ परीक्षण आदि की कागजात का रिनुअल डेट फेल हो चुका था। इस दौरान ऐसे वाहनों को पुलिस प्रशासन के द्वारा नोटिस के साथ यह निर्देश दिया गया की 7 दिनों के अंदर इन सब कागजातों को सही कर लिया जाए। साथ ही वाहन को फिटनेस कर दिया जाए ।अन्यथा बाद में बहुत सख्त कार्रवाई होगी। वहीं इस निर्देश के बाद पुलकारों के चालकों एवं मालिकों ने कहा कि हम लोग हम सभी निर्देश को पालन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभिभावकों के द्वारा भाड़ा नहीं बढ़ाई जा रही है। जिससे हम लोग असमर्थ हैं। क्योंकि हम लोग 50 या ₹100 भाड़ा बढ़ाने की मांग करते हैं। हम लोग एक हजार रुपया कहते हैं तो अभिभावकों को कहना है कि ₹500 में टोटो स्कूल तक पहुंचा देती है तो मैं आप लोगों को ₹1000 क्यों दूं ।दो अभिभावक भाड़ा देने के तैयार होते हैं और आठ अभिभावक नहीं होते हैं।

वे लोग टोटो में चले जाते हैं ।ऐसी स्थिति में हम लोग तेल का भी दाम नहीं निकाल पाते हैं।यदि अभिभावक भाड़ा नहीं बढ़ायेंगे तो हम लोग गाड़ी कैसे चलाएंगे। अपने परिवार को कैसे चलाएंगे और इन निर्देशों को कैसे हम लोग मेंटेनेंस कर पाएंगे। यह बहुत बड़ी समस्या की बात है।वही मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर ने कहा कि सभी पुलकार वाहनों को निर्देश दे दिया गया है कि वह परिवहन विभाग के नियमों का पालन करें। उसके निर्देश को पालन करते हुए अपने वाहन को सुरक्षित करें। ताकि छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो पाए। यदि वे लोग इस निर्देश का पालन नहीं करेंगे तो सख्त कार्रवाई होगी।

नेक्स्ट-जेन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के क्षेत्र में नया कदम

- दुर्गापुर एनआईटी को मिला 1.13 करोड़ का इंटरनेशनल प्रोजेक्ट

निज संवाददाता : नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआइटी) दुर्गापुर को नेक्स्ट-जेनरेशन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए 1.13 करोड़ रुपये का इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिला है। एसपीएआरसी ऐप्स कमेटी ने आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट पी-4015 को मंजूरी दे दी है। यह उपलब्धि संस्थान के लिए गर्व का विषय है।

सेमीकंडक्टर रिसर्च में बड़ी उपलब्धि

''ईईई-वी और ईईई-एनएमओएस प्लेटफॉर्म के लिए हाइब्रिड नैनो-पिलर डाइइलेक्ट्रिक स्टैक्स'' नामक यह प्रोजेक्ट हाई-स्पीड और मल्टी-फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विकसित करने पर केंद्रित है, जिनका उद्देश्य पारंपरिक सिलिकॉन आधारित तकनीक की सीमाओं को पार करना है। ''आत्मनिर्भर भारत'' मिशन को बढ़ावा देते हुए संस्थान को स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन (एसपीएआरसी) फेज़-4ए के तहत 21.13 करोड़ रुपये का रिसर्च ग्रांट भी प्रदान किया गया है।

भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बल : एनआइटी दुर्गापुर के डायरेक्टर प्रो अरविंद चौबे ने कहा कि यह हाई-वैल्यू इंटरनेशनल कोलैबोरेशन न केवल ''मेक इन इंडिया'' पहल को मजबूती देता है, बल्कि एनआइटी दुर्गापुर को एडवांस्ड मटीरियल रिसर्च के एक महत्वपूर्ण हब के रूप में स्थापित करता है। उन्होंने बताया कि ताइवान और रूस जैसे वैश्विक सहयोगियों के साथ मिल कर काम करना इस बात का प्रमाण है कि संस्थान के विद्यार्थी व फैकल्टी अत्याधुनिक तकनीक पर काम कर रहे हैं।

'आमादेर पाड़ा अमादेर समाधान' के कार्यों को गति देने को

मेयर ने 10 बोरो चेयरमैन के साथ की बैठक

निज संवाददाता : वर्ष 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा की चुनाव होने वाला है। उसके पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की महत्वपूर्ण योजना 'आमदेर पाड़ा अमादेर समाधान' के तहत हर बूथ की समस्याओं को हल करने के लिए लिए एक योजना चलाई गई थी। जिसमें मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि प्रत्येक बूथ की समस्याओं को हल करने के लिए 10 लाख रुपया दिया जाएगा। इसके तहत आसनसोल नगर निगम में भी कैंप लगाकर नगर निगम के सभी 106 वार्डो के प्रत्येक बूथ की समस्या का आवेदन लिया गया था। लेकिन अभी तक इस योजना के तहत कार्य शुरू नहीं हुआ है। इन कार्यों को करने के लिए शुक्रवार को आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने नगर निगम के सभी 10 बोरो के चेयरमैन को लेकर नगर निगम में एक बैठक की। जिसमें जल्द से जल्द इस योजना के तहत जो कार्य दिया गया है, उसे पूरा करने के लिए पहल की गई। इस संबंध में मेयर ने बताया कि आज 'आमादेर पाड़ा अमादेर समाधान' के तहत जो कार्य करना है उसको लेकर सभी 10 बोरो के चेयरमैन को लेकर एक बैठक की गई। सभी 106 वार्डो से 3600 कार्य का आवेदन आया है, जिसमें 3100 कार्यों की टेंडर प्रक्रिया चल रही है। वहीं एक सौ कार्य के लिए वर्क आर्डर जारी कर दिया गया है। जल्द ही सभी 3600 कार्यों के लिए वर्क आर्डर पास कर दिया जाएगा।

बाबरी मस्जिद निर्माण के ऐलान के बाद नये समीकरण की संभावना

हुमायूं कबीर बने किंगमेकर तो बीजेपी बन सकती है बंगाल का बॉस

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल में अगले मार्च-अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है। यह अयोध्या में ध्वस्त की गई बाबरी मस्जिद जैसी होगी, जिसे तृणमूल कांग्रेस से निलंबित किए गए विधायक हुमायूं कबीर बना रहे हैं। भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर 22 दिसंबर को नई पार्टी का ऐलान करेंगे। उनकी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएआईएम (एआईएआईएम) से गठबंधन करेगी। हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनिंदा 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद वह किंगमेकर बनेंगे। इसका दूसरा पहलू भी है, हुमायूं कबीर अगर किंगमेकर बने तो बीजेपी बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। अभी हुमायूं कबीर का किंगमेकर बनने का दावा पहली नजर में राजनीतिक स्टंट नजर आ रहा है। मगर उन्होंने मस्जिद, मुसलमान और ओवैसी का जो पॉलिटिकल कॉकटेल बनाया है, उससे पश्चिम बंगाल में नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं। बिहार चुनाव के बाद असदुद्दीन ओवैसी ऐसे मुस्लिम नेता के तौर पर उभरे हैं, जिनकी स्वीकार्यता हैदराबाद के बाहर अन्य राज्यों में बढ़ी है। 2011 से बंगाल के मुस्लिम वोटर हर चुनावों में तृणमूल कांग्रेस के पाले में रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ सशक्त विपक्ष को समर्थन करने के ट्रेंड ने मुसलमानों को पहले ही लेफ्ट-कांग्रेस से दूर कर दिया है। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने 6 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, मगर मुसलमान टीएमसी के पक्ष में बने रहे। अब हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद वाला तत्व डालकर नया प्रयोग किया है। हुमायूं कबीर को उम्मीद है कि 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा का परिणाम 2026 में टीएमसी के पक्ष में एकतरफा नहीं रहेगा। इस कारण उन्हें किंगमेकर बनने का मौका मिलेगा। दरअसल, हुमायूं कबीर का कैलकुलेशन बंगाल में मुस्लिम आबादी और मुसलमान बाहुल्य सीटों के आंकड़े के हिसाब से फिट बैठता है, बशर्ते वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए। पश्चिम बंगाल में 30 फीसदी मुसलमानों की आबादी माना जाती है और करीब 120-126 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक माने जाते हैं। 50 फीसदी से ज्यादा आबादी वाली 45 विधानसभा सीटें हुमायूं कबीर के उम्मीदों को मजबूत करती है। इसके अलावा 16 सीटें ऐसी हैं, जहां 40 से 50 पर्सेंट वोटर मुस्लिम हैं। 135 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हुमायूं कबीर अगर मुस्लिम नेता के तौर पर स्वीकार्य होते हैं तो वह करीब 60 सीटों पर टीएमसी को सीधे परेशान कर सकते हैं। हुमायूं कबीर को किंगमेकर बनने के परिप्रेक्ष्य में 2021 के चुनाव परिणाम को जानना जरूरी है। विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 148 है। पिछले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को 215 सीटें मिली थीं, जो बहुमत से 67 सीटें ज्यादा हैं। पहली स्थिति यह बनती है कि टीएमसी को 100 के करीब सीटों का नुकसान हो और हुमायूं कबीर 40-45 सीटें हासिल करे तभी वह सत्ता में निर्णायक होंगे। अगर टीएमसी को इतना भारी नुकसान हुआ तो निश्चित तौर से बीजेपी को 50 से अधिक सीटों का फायदा होगा। बीजेपी 77 से बढ़कर 125-130 के आसपास पहुंचकर नंबर वन पार्टी बन जाएगी। जो अभी के माहौल में सामान्य तौर पर संभव नहीं है। ऐसा तभी हो सकता है, जब मुस्लिम वोटर पूरी तरह हुमायूं कबीर के पक्ष में जाएं और बीजेपी को हिंदू बाहुल्य वाले 165 सीटों पर बड़ी जीत मिले। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने राज्य के दो राजनीतिक इलाकों राढ़ बंगा और दक्षिण बंगाल में बड़ी बढ़त हासिल की थी। उत्तर बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी से ज्यादा सीटें जीती थी।

हिन्दुओं की आस्था को रौंद कर आगे बढ़ने की कट्टरपंथी सोच

निज संवाददाता : हिन्दुस्तान मुसलमानों की जहनियत में पिछले चार-पांच दशकों से काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और संविधान से चलता है, लेकिन अब देश के मुसलमानों में भारत के प्रति वैसी वफादारी नहीं दिखती जैसी उनके मन में शरीयत के प्रति है। कहने को तो शरीयत कुरान की ही सोच है, लेकिन हकीकत यह है कि कट्टरपंथियों ने शरीयत में कुरान के कई संदेशों को अनदेखा कर दिया है। इसलिए देश में कभी वंदेमातरम और भारत माता की जय पर बवाल होता है तो कभी हिन्दुओं के प्रति घृणा फैलाई जाती है। उनकी भावनाओं को आहत किया जाता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में, तीन साल पहले की वह सुबह भूलना मुश्किल है। ईद की नमाज़ के बाद सड़क पर उमड़ी भीड़ अचानक नारों से गूंज उठी। 'भारत माता की जय' बोलने वाले हिंदू पड़ोसियों को घेर लिया गया। पत्थर चले, गाड़ियां जलाई गईं। वजह? बस एक पुरानी मस्जिद के पास लगे राष्ट्रगान के पोस्टर। स्थानीय मुस्लिम युवाओं का कहना था कि वे 'काफिरों के नारे' नहीं बर्दाश्त करेंगे। पुलिस ने बाद में पकड़े गए 40 लोगों में से ज्यादातर को जमानत मिल गई, लेकिन वह घटना पूरे इलाके में दरार डाल गई। आज भी वह कस्बा दो खेमों में बंटा है। यह एक छोटी सी मिसाल है उस बदलाव की, जो आजादी के बाद भारत के मुसलमानों की सोच में आया है।

बात 1947 की है, जब आजादी की दहलीज पर खड़ा भारत दो टुकड़ों में बंट गया। मुहम्मद अली जिन्ना की ज़िद्द ने पाकिस्तान को जन्म दिया, इस्लाम के नाम पर। हिंदुओं, सिखों के लिए बचा भारत। बंटवारे का सिद्धांत साफ़ था, मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन लाखों मुसलमानों ने इनकार कर दिया। उनका तर्क था, हम भारत से मोहब्बत करते हैं। यहां लोकतंत्र है, संविधान बनेगा, कानून राज करेगा। शरीयत की हुकूमत नहीं चाहिए। नेहरू, पटेल जैसे नेताओं ने इन्हें आश्वासन दिया। नतीजा? 1947 में भारत में 3.5 करोड़ मुसलमान रह गए, जबकि पाकिस्तान चला आधा करोड़। आज यह संख्या 20 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। तत्पश्चात पहले दो दशक शांतिपूर्ण गुज़रे। मुसलमानों ने भारतीय सेना में हिस्सा लिया, बॉलीवुड सितारे बने, खिलाड़ी हुए। लेकिन 1970 के बाद हवा बदली। खाड़ी युद्धों ने पैसे लाए, सऊदी से वहाबी विचारधारा घुस आई। मदरसों की संख्या 1981 में 900 से बढ़कर 2023 तक 2.7 लाख हो गई। इनमें से 25 हज़ार से ज़्यादा बिना पंजीकरण के चलते हैं। आजकल शरीयत की मांग, 'ग़ज़वा ए हिंद' के नारे सुनाई देते हैं। सोशल मीडिया पर हिंदू देवताओं के खिलाफ नफरत भरी पोस्टें वायरल होती हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय जैसे नारे तक असंवैधानिक बता दिए जाते हैं। तुष्टिकरण की सियासत करने वाले नेताओं और राजनीतिक दलों द्वारा इस तरह की गतिविधियों से मुंह मोड़ लिया जाता है।

भारतीय राजनीति में यह सब कई दशकों तक साफ दिखता है। हिन्दू वोटरों को जाति के नाम पर बांट दिया जाता था और मुस्लिमों को एकजुट किया जाता रहा, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से भारत की सियासत की तस्वीर काफी बदल गई। अब मुस्लिमों की तरह हिन्दू भी एकजुट होकर वोटिंग करने लगे हैं। यही वजह थी कि 2014 में देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। इसके बाद यही पैटर्न कई विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दिया, जहां हिन्दू बहुमत में भाजपा को समर्थन देते हैं, वहां मुसलमान एकजुट होकर विरोध करते हैं। परंतु गैर भाजपाई दलों ने हिंदुओं को बांटने की कोशिश छोड़ी नहीं। कभी बीजेपी के खिलाफ यादव-मुस्लिमों को एकजुट करने की कोशिश होती तो कभी दलित-मुसलमानों को एक बैनर तले लाने की नाकाम कोशिश की जाती। 2019 लोकसभा में 27 फीसदी मुस्लिम बहुल सीटों पर विपक्ष ने सिर्फ़ इसलिए जीत हासिल की क्योंकि वोट ट्रांसफर हुआ। भाजपा को हराने का एकमात्र मकसद तुष्टिकरण वाली पार्टियां ही सत्ता में रहें। यही पैटर्न पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी के विधानसभाओं में दिखा। 2022 यूपी चुनाव में 17 फीसदी मुस्लिम वोटों ने भाजपा को 60 से ज़्यादा सीटें कम करा दीं। दुनिया भर के मुसलमानों से भारत के मुसलमानों की तुलना करें तो भारत का मुसलमान सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक जिंदगी जीता है। पहला, लोकतंत्र। भारत में हर नागरिक को वोट का हक़। पाकिस्तान में 2024 चुनावों में 40 फ़ीसदी वोटिंग हुई, सेना ने असल में सरकार बनाई। बांग्लादेश में हसीना की हुकूमत ने विपक्ष को कुचल दिया। अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं को घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी। भारत में मुस्लिम महिलाएं चीफ जस्टिस तक बनीं।

दूसरा, धार्मिक आज़ादी। संविधान के अनुच्छेद 25-28 हर मजहब को मानने, प्रचार करने का हक़ देते हैं। भारत में 4 लाख से ज्यादा मस्जिदें, 2.7 लाख मदरसे। केंद्र सरकार ने 2023 में 5 हज़ार करोड़ मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए दिए। सऊदी में गैर इस्लामी पूजा पर कोड़े लगते हैं। मिस्र में कॉप्टिक चर्च सीमित। भारत में हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण, लेकिन वक्फ बोर्ड स्वायत्त।

तीसरा, वक्फ संपत्ति। आज 32 राज्य के वक्फ बोर्डों के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन, करीब मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपये की है। दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं। पाकिस्तान का वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार में डूबा। भारत में यह संपत्ति मुस्लिम कल्याण के लिए आरक्षित। हालांकि, 58 हज़ार संपत्तियों पर विवाद, लेकिन कानूनी सुरक्षा बरकरार।

चौथा, व्यक्तिगत कानून। भारतीय मुसलमानों को शरीयत आधारित विवाह, तलाक, उत्तराधिकार का हक़ है। हज सब्सिडी 2018 तक 7000 करोड़ खर्च होती है। ट्रिपल तलाक पर कानून बना, लेकिन बहुविवाह वैध है। हिंदुओं पर 1955 से साझा कानून। ईरान में शरीयत सख्त, लेकिन भारत जैसी छूट नहीं।

पांचवां, अभिव्यक्ति। भारत में मुसलमान सड़कों पर सीएए के विरोध में 100 दिन धरना देते हैं। 2020 दिल्ली दंगों में 50 से ज़्यादा प्रदर्शन होते हैं। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी कानून पर 1500 मुकदमे, 80 हत्याएं। भारत में ओवैसी जैसे नेता संसद में सरकार को ललकारते हैं।

छठा, शिक्षा और रोजगार। अल्पसंख्यक कोटा से एएमयू, जामिया में 50 फ़ीसदी आरक्षण। 2023 में यूपीएससी में 20 मुस्लिम आईएएस, भारतीय सेना में 3 फ़ीसदी मुस्लिम अधिकारी। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन जैसे उदाहरण। यूएई में हिंदू मंदिर 2023 में बना, लेकिन भारत जितनी आजादी नहीं।

सातवां, न्यायपालिका। मुस्लिम जज सुप्रीम कोर्ट में। 2024 तक 10 फीसदी हाईकोर्ट जज। बाबरी मस्जिद केस में 10 साल सुनवाई, शांति से फैसला। तुर्की में आया सोफिया मस्जिद बनी, लेकिन भारत जैसा धैर्य नहीं।

बहरहाल, इन सुविधाओं के बावजूद समस्या कहां? 2023 एनसीएपी डेटा में आतंकी मॉड्यूल में 80 फ़ीसदी भारतीय मुस्लिम। आईएसआई से फंडिंग वाले 500 से ज्यादा मदरसे। 'ग़ज़वा ए हिंद' के 10 हज़ार से ज़्यादा प्रचारक। पाकिस्तान के लिए सहानुभूति, 26/11 हमले पर भी कुछ मौलानाओं ने इसे विद्रोह कहा। संविधान कहता है, भारत सर्वोपरि। लेकिन जब पड़ोसी दुश्मन देशों के हित साधे जाते हैं, काफ़िरों से नफ़रत फैलाई जाती है, तो चिंता बढ़ती है। 75 सालों में भारत ने सब दिया, वोट, मस्जिदें, कानून। अब ज़िम्मेदारी मुस्लिम समाज की है। क्या वे शरीयत छोड़कर संविधान अपनाएंगे? या ग़ज़वा के ख़्वाब देखते रहेंगे? लब्बोलुआब यह है कि भारत के बहुसंख्यक समाज को भी सावधान रहना होगा। नफरत का जवाब नफरत नहीं। लेकिन तुष्टिकरण बंद। कट्टरपंथ पर जीरो टॉलरेंस। जब तक मुसलमान खुद न कहें, ''हम पहले भारतीय, फिर मुसलमान,'' तब तक दरारें बढ़ेंगी। भारत का भविष्य एकता पर टिका है, नफरत पर नहीं। यह बात उन मुसलमानों को आगे बढ़कर बतानी होगी जो देश का भला चाहते हैं।

18 दिसंबर को 'धन धान्य' स्टेडियम में ममता करेंगी बिजनेस एंड इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का उद्घाटन

सम्मेलन में रहेगा 8 इंडस्ट्रियल सेक्टर पर फोकस

निज संवाददाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगामी 18 दिसंबर को महानगर के धन धान्य स्टेडियम में बिजनेस एंड इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगी। इसमें 8 इंडस्ट्रियल सेक्टर पर खास जोर दिया जाएगा, जिनमें स्टील, जेम्स एंड ज्वेलरी, फूड प्रोसेसिंग, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, टूरिज्म और टेक्सटाइल प्रमुख हैं। हालांकि, सम्मेलन में दूसरे सेक्टर भी होंगे। यह कॉन्क्लेव धन धान्य स्टेडियम में होगा। माना जा रहा है कि यह राज्य में निवेश और रोजगार के रास्ते को और विस्तार देने में अहम भूमिका निभाएगा। इस कॉन्क्लेव की आखिरी तैयारी बैठक बीते शुक्रवार को नवान्न में हुई। राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत, मुख्यमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार अमित मित्रा और प्रशासन के दूसरे अहम अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 18 दिसंबर को धन धान्य स्टेडियम में बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगी। इसमें राज्य के सभी बड़े उद्योगपति मौजूद रहेंगे। नवान्न सूत्रों के मुताबिक, कॉन्क्लेव के पहले फेज में मुख्यमंत्री औद्योगिक नक्शे पर पश्चिम बंगाल की तरक्की और निवेश को हाईलाइट करेंगी। हर्ष नेवटिया, संजीव गोयनका, रुद्र चटर्जी, संजय बुधिया, उमेश चौधरी और दूसरे जाने-माने उद्योगपति बंगाल में उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार के समर्थन पर बात करेंगे। इस बिज़नेस कॉन्क्लेव के दूसरे फेज़ में विश्व बैंक की मदद से राज्य में चल रहे प्रोजेक्ट्स पर एक प्लेनरी सेशन होगा। विश्व बैंक की मदद से राज्य में अभी चल रहे प्रोजेक्ट्स में खास हैं कोलकाता और उसके आस-पास के इलाकों में वॉटरवे ट्रांसपोर्ट का मॉडर्नाइज़ेशन, सुंदरबन में नदी के रास्तों का रेनोवेशन और वहां के आइलैंड्स में रहने वालों की ज़िंदगी की क्वालिटी में सुधार, दामोदर बेसिन में बाढ़ कंट्रोल और सिंचाई सर्विस का डेवलपमेंट। पता चला है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर कॉन्क्लेव के लिए इंडस्ट्री के आठ क्षेत्रों को खास तौर पर चुना गया है। जिनमें सबसे अहम हैं टूरिज्म, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टील, एआई शामिल हैं। इसके अलावा, राज्य लेदर, मेडिसिन और दवा से जुड़े अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ को भी अहमियत दे रहा है। इन आठ सेक्टर से जुड़े डिपार्टमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप लेवल से इन सेक्टर की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए अलग-अलग प्रेजेंटेशन तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कॉन्क्लेव में मेहमानों को अच्छे से समझाया जाएगा कि राज्य इन क्षेत्रों को क्यों महत्व दे रहा है।

बंगाल में करीब 1 करोड़ 67 लाख 45 हजार 911 फॉर्म में गड़बड़ी पाई गई

एसआईआर फॉर्म को लेकर चुनाव आयोग ने किया खुलासा

निज संवाददाता : चुनाव आयोग ने कई राज्यों में एसआईआर फॉर्म भरने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है, लेकिन पश्चिम बंगाल, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और राजस्थान में एसआईआर फॉर्म भरने की तारीख बीते गुरुवार को समाप्त हो गई और इन राज्यों में ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 16 दिसंबर को प्रकाशित किए जाएंगे। इस बीच, पश्चिम बंगाल में भरे गए एसआईआर फॉर्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। चुनाव आयोग के अनुसार करीब 1 करोड़ 67 लाख 45 हजार 911 फॉर्म में गड़बड़ी पाई गई है। चुनाव आयोग को वोटर्स द्वारा दी गई जानकारी पर शक है। चुनाव आयोग इन मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुला सकता है।

चुनाव आयोग की ओर से मिले आंकड़ों के अनुसार करीब 85 लाख वोटर्स के पिताओं के नाम में गड़बड़ी सामने आई है। करीब 13.5 लाख वोटर्स के माता-पिता एक ही हैं। इनमें से 11 लाख 95 हजार वोटर्स 15 साल की उम्र से पहले पिता बन गए हैं।

चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में 6 बच्चों के पिताओं की संख्या 24 लाख 21 हजार है। आंकड़ों के अनुसार 3 लाख 45 हजार 40 साल की उम्र से पहले दादा बन गए।यानी, अगर पूरे आंकड़ों की तुलना की जाए और डिटेल्ड जानकारी वेरिफाई की जाए, तो पता चलता है कि राज्य में 13.5 लाख वोटर्स के मामले में पिता और माता के तौर पर एक ही व्यक्ति का नाम आया है। यानी, किसी परिवार में एक के मामले में, उस परिवार में मां की जगह पिता का नाम आया है, तो किसी के मामले में, मां की जगह पिता का नाम आया है। चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार राज्य में 11 लाख 95 हजार 230 वोटर्स के बेटे अपने पिता से 15 साल छोटे हैं। वहीं, 3 लाख 29 हजार 152 वोटर्स 40 साल की उम्र से पहले ही दादा बन गए हैं। चुनाव आयोग को उनकी जानकारी, यानी उनकी उम्र को लेकर शक है। चुनाव आयोग के अनुसार इन 1 करोड़ 67 लाख से ज्यादा वोटर्स में से कुछ, जिनके नाम और उम्र गलत हैं, उन्हें हियरिंग के लिए बुलाया जा सकता है। कमीशन के सूत्रों के मुताबिक, इन सभी वोटर्स की जानकारी फिर से वेरिफाई की जाएगी। बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर जाकर जानकारी वेरिफाई करेंगे और फिर उन्हें हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा। इस मामले में रोल ऑब्जर्वर का रोल भी बहुत अहम है। इस मामले पर बीजेपी के प्रवक्ता देबजीत सरकार ने कहा-असल में यह पूरी बात फेक है। कई बार लेफ्ट और फिर तृणमूल ने चुनाव जीतने के लिए आम लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। उन्होंने असली वोटर्स को वोट नहीं देने दिया, जो लोग पिछले 15 सालों में पिता बने हैं, वे असल में घोस्ट वोटर बन गए हैं और इन लोगों को जिताया है। दूसरी ओर, तृणमूल प्रवक्ता तन्मय घोष ने कहा, जहां पिता के नाम में गलती है, जहां कई मामलों में पिता का नाम एक ही है, इन सबकी जांच करना इलेक्शन कमीशन का काम है। यह पूरे साल से हो रहा है। अगर ऐसी कोई जानकारी सामने आई है, तो उसे हटा दिया जाएगा।

एसआईआर में ममता बनर्जी के विधानसभा केंद्र से काटे गए 44,787 वोटरों के नाम

- शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन क्षेत्र से चार गुना अधिक है यह संख्या

निज संवाददाता : बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) की प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। चुनाव आयोग द्वारा बीते शुक्रवार को इसे लेकर आंकड़े जारी किए। निर्वाचन क्षेत्र-वार आंकड़ों के अनुसार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में राज्य में सबसे अधिक वोटरों के नाम हटाए गए हैं। यह संख्या नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र की तुलना में लगभग चार गुना अधिक बताई जा रही है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद राज्य की सियासत में नया मोड़ आ गया है, खासकर ऐसे समय में जब अगले सप्ताह ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने वाली है।

चुनाव आयोग ने यह डेटा एसआईआर प्रक्रिया के तहत गणना फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के एक दिन बाद सार्वजनिक किया। आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण कोलकाता स्थित भवानीपुर में जनवरी 2025 तक कुल 2,06,295 पंजीकृत मतदाता थे, जिनमें से 44,787 नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। इसके मुकाबले नंदीग्राम में, जहां कुल 2,78,212 मतदाता दर्ज थे, केवल 10,599 नाम हटाए गए। आयोग ने स्पष्ट किया है कि हटाए गए नामों को मौत, स्थान परिवर्तन, पता न मिलना और डुप्लीकेट एंट्री जैसी मानक श्रेणियों में रखा गया है और पूरी प्रक्रिया में राज्यभर में समान मानदंड अपनाए गए।

हालांकि भवानीपुर राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, लेकिन यह नाम हटाने के मामले में राज्य में शीर्ष पर नहीं है। 294 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक नाम उत्तर कोलकाता के चौरंगी विधानसभा क्षेत्र से हटाए गए, जहां 74,553 मतदाताओं के नाम सूची से बाहर किए गए। यह सीट तृणमूल कांग्रेस की विधायक नयना बंद्योपाध्याय के पास है, जिन्होंने 2021 के चुनाव में 44 हजार से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। इसी तरह कोलकाता पोर्ट विधानसभा क्षेत्र, जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम करते हैं, वहां 63,730 नाम हटाए गए। मंत्री अरूप विश्वास के टॉलीगंज क्षेत्र में 35,309 नाम हटाए गए, जबकि श्यामपुकुर से 42,303 और बालीगंज से 65,171 नाम हटाए गए। बालीगंज का प्रतिनिधित्व मंत्री बाबुल सुप्रियो करते हैं, जो पहले भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं।

इसी तरह, बीजेपी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में नाम हटे हैं। आसनसोल दक्षिण, जहां से भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल निर्वाचित हुई थीं, वहां 39,202 नाम हटाए गए। सिलीगुड़ी, जो उत्तर बंगाल में भाजपा की अहम सीट मानी जाती है और जहां विधायक शंकर घोष हैं, वहां 31,181 नाम हटाए गए। जिला स्तर पर देखें तो दक्षिण 24 परगना जिला सबसे आगे रहा, जहां कुल 8,16,047 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। यह जिला तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का मजबूत गढ़ माना जाता है। वहीं सबसे कम नाम बांकुड़ा जिले के कोतुलपुर विधानसभा क्षेत्र में हटाए गए, जहां यह संख्या 5,678 रही।

कुल मिलाकर, एसआईआर प्रक्रिया के पहले चरण में राज्यभर में 58 लाख से अधिक नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं। चुनाव आयोग मंगलवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा, जिसके बाद आपत्तियों और दावों की प्रक्रिया शुरू होगी। इन आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कृषाणु मित्रा ने कहा कि पार्टी डेटा की गहन समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि यदि मृत या स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि किसी वास्तविक मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेगी।

वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक शंकर घोष ने कहा कि ये आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि राज्य में एसआईआर प्रक्रिया क्यों जरूरी थी। उनके मुताबिक इससे फर्जी मतदाताओं की संख्या सामने आई है, जो लंबे समय से तृणमूल की राजनीतिक ताकत का हिस्सा रहे हैं।

बाबरी मस्जिद विवाद पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता पर साधा निशाना

'बंगाल को बांग्लादेश बनाने की हो रही साजिश'

निज संवाददाता : टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखी है, जिसे लेकर राजनीतिक घमासान थमता नहीं दिख रहा। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने इस मुद्दे पर रिएक्ट किया है। उन्होंने पश्चिमी मेदिनीपुर में कहा कि अगर पूरे देश में कहीं भी बाबरी मस्जिद नहीं है, तो बंगाल में इस नाम से मस्जिद क्यों बनाया जा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां बांग्लादेश बनाने की साजिश चल रही है, और यह ममता बनर्जी का तोहफा है। मस्जिद बनाना गलत नहीं है, लेकिन आप इसे बाबर के नाम पर क्यों बना रहे हैं? बाबर एक अत्याचारी था, आक्रांता था। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के नेता दिलीप घोष ने कहा कि बाबरी मस्जिद वाला कॉन्सेप्ट है, उसको यहां की जनता ने साफ कर दिया। अदालत के आदेश से मंदिर बन गया राम जी का, लेकिन बंगाल में क्यों बाबरी मस्जिद बन रही, क्योंकि इसे बांग्लादेश बनाने की साजिश हो रही। ये जो पूरा ड्रामा था, वो एक्सपोज हो गया। ममता बनर्जी का पूरे मामले में जो पीछे से हाथ है वो भी साफ हो गया। यही वजह है कि लोगों का आग्रह कम हो गया।

दिलीप घोष ने कहा कि मस्जिद बनाने में आपत्ति नहीं है। अभी तो जहां ये मस्जिद बन रही उसकी जमीन ही ठीक नहीं है। बनाओ मस्जिद लेकिन कोई बाबर के नाम से नहीं बनाओ। बाबर कौन होता है हमारे देश का, वो अत्याचारी था, आकांता था। उसके साथ क्यों मस्जिद को जोड़ रहे हैं। यहां के समाज के साथ जोड़िए। मस्जिद बनाइए, अपने धर्म का पालन करिए कौन मना करता है।

आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि नागरिकों को राष्ट्रीय हित में जीना चाहिए और राष्ट्र सर्वप्रथम होना चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने वीर सावरकर को देशभक्ति के लिए याद करते हुए देशवासियों से कहा कि अब राष्ट्र के लिए जीने का समय है। इस पर भी बीजेपी नेता दिलीप घोष ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि सरसंघचालक बार-बार देशवासियों को राष्ट्र सर्वप्रथम की याद दिलाते हैं। नागरिकों को राष्ट्रीय हित में जीना चाहिए। आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अवसर पर खुद सरसंघचालक मोहन भागवत लोगों को जागरुक करने का काम कर रहे हैं। इससे पूरे देश में सकारात्मक माहौल बनेगा और एक मजबूत व विकसित राष्ट्र के निर्माण में मदद मिलेगी। इसी बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी हमेशा धमकाती रहती हैं। उनकी धमकी के कारण कई बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) आत्महत्या कर रहे हैं। ममता बनर्जी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि अभी तक तकरीबन 58 लाख फर्जी मतदाताओं को सूची से हटाया जा चुका है। फाइनल सूची में लगभग इतने और फर्जी मतदाताओं के नाम हटेंगे। इसी से ममता बनर्जी डरी हुई हैं और दूसरों को भी डरा रही हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग जागरुक हैं। सत्तापक्ष की तरफ से भ्रमित करने के बावजूद लोगों ने फॉर्म जमा किए हैं। संसद परिसर में कथित तौर पर टीएमसी सांसद के ई-सिगरेट पीने वाले विवाद पर दिलीप घोष ने कहा कि ये तृणमूल की संस्कृति है। संवैधानिक पदों पर रहे लोगों का अपमान करना, हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का सम्मान न करना, कानून के खिलाफ काम करना। एक सांसद इस तरह कैसे व्यवहार कर सकता है? पश्चिम बंगाल में ये संस्कृति भ्रष्ट हो चुकी है और ये पूरे देश को नुकसान पहुंचा रही है। इनकी भाषा और व्यवहार अत्यंत निंदनीय है।

नफरत पर भारी पड़ीं इंसानियत

सिडनी : रविवार को सिडनी के बॉन्डी बीच पर मानवता के दो विपरीत चेहरे देखने को मिले। एक तरफ नफरत की आग थी, तो दूसरी तरफ बेमिसाल इंसानियत का जज्बा। इस खौफनाक हमले के बाद दो नाम सामने आए नवीद अकरम और अहमद अल-अहमद। भले ही उनके नाम एक जैसे लग सकते हैं या उनकी जड़ें एक ही सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हों, लेकिन रविवार की शाम ने यह साबित कर दिया कि इंसान की असली पहचान उसके नाम या धर्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म और संस्कारों से होती है। एक शख्स हाथ में राइफल लेकर बेगुनाहों के खून का प्यासा बनकर आया था, तो दूसरा, निहत्था होकर भी, उसी मौत के सामने चट्टान बनकर खड़ा हो गया। रविवार शाम को ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर यहूदी समुदाय हनुक्का त्योहार मना रहा था, खुशियां बांट रहा था। तभी 24 वर्षीय नवीद अकरम, हथियारों से लैस होकर वहां पहुंचा। उसका एकमात्र मकसद नफरत फैलाना और मासूमों की जान लेना था। उसने 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और वह हैवानियत का चेहरा बन गया। लेकिन ठीक उसी वक्त, वहां 43 वर्षीय अहमद अल-अहमद भी मौजूद थे। पेशे से फलों की दुकान चलाने वाले एक आम इंसान। गोलियां चलने के बावजूद, अहमद भागे नहीं। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना, हमलावर या पीड़ितों के धर्म की परवाह किए बिना, केवल इंसान और इंसानियत की रक्षा का फैसला किया। रिपोर्ट्स के अनुसार, हमलावर नवीद अकरम पाकिस्तानी मूल का 24 वर्षीय युवक था। उसने प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की थी, उसके पास डिग्रियां थीं और जिंदगी जीने के कई अवसर थे। लेकिन उसके दिमाग में भरी नफरत ने उसे इस रास्ते पर धकेल दिया। उसने अपनी शिक्षा का उपयोग दुनिया को बेहतर बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसे बर्बाद करने के लिए किया। उसने एक ऐसे त्योहार को चुना जो उम्मीद और रोशनी का प्रतीक है, और उसे खून से रंग दिया। नवीद अकरम उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है जो मानती है कि अपने विचारों को थोपने के लिए किसी की जान लेना जायज है। वह एक क्रूर हत्यारा था, जो शिक्षा के बावजूद नैतिक रूप से जाहिल साबित हुआ। दूसरी तरफ, अहमद अल-अहमद हैं। वह कोई कमांडो नहीं, बल्कि एक साधारण पिता हैं और फलों की दुकान चलाते हैं। शायद उनकी शैक्षणिक योग्यता नवीद जितनी भारी न हो, लेकिन उनके संस्कार नवीद से कहीं ज्यादा ऊंचे साबित हुए। जब नवीद अकरम अपनी राइफल से आग उगल रहा था, तब सफेद शर्ट पहने अहमद ने जो किया, वह अद्वितीय साहस का प्रतीक है। वीडियो फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अहमद ने अपनी जान की बाजी लगाकर नवीद को पीछे से दबोचा, उसे जमीन पर पटक दिया और उसके हाथ से राइफल छीन ली। यदि अहमद उस निर्णायक पल में हिम्मत न दिखाते, तो शायद मरने वालों का आंकड़ा और भी भयावह होता। उन्होंने यह नहीं सोचा कि हमलावर हथियारबंद है। उन्होंने बस यह सोचा कि सामने खड़े लोग खतरे में हैं।

बीजेपी ने टीएमसी प्रमुख पर किया बड़ा हमला

- ममता बनर्जी की तुलना हिटलर से की

निज संवाददाता : बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला किया है। बीजेपी ने ममता की तुलना जर्मनी के तानाशाह हिटलर से की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पश्चिम बंगाल बीजेपी की तरफ से एक पोस्ट साझा की गई है। इसमें बीजेपी ने कहा है दोनों एक ही हैं। इसके साथ बीजेपी ने लिखा है कि तानाशाह घबरा गया है। बीजेपी ने ममता पर हमले ऐसे वक्त पर वक्त पर किया है जब राज्य में चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जानी है। आयोग ने बंगाल में बिहार से भी अधिक नाम मतदाता सूची से काटे हैं। कुल 58 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। ममता की अपनी विधनसभा सीट भावानीपुर में भी 40 हजार से ज्यादा वोट डिलीट हुए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में अब सिर्फ दो से तीन महीने वक्त बच है। मार्च-अप्रैल में चुनाव होने की उम्मीद की जा रही है। पिछले चुनावों में सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला हुआ था, हालांकि अभी तक राज्य की सत्ता पर काबिज टीएमसी ने हर बार अपनी सीटों की संख्या बढ़ाई है लेकिन बीजेपी ने पिछले चुनावों के अप्रत्याशित तौर पर 77 सीटें जीती थीं, हालांकि पिछले पांच सालों में काफी विधायकों के वापस टीएमसी में जाने पर बीजेपी के मौजूदा विधायकों की संख्या 63 है। विधानसभा चुनावों के हाई वोल्टेज होने की उम्मीद की जा रही है। बीजेपी पहले भी ममता के तानाशाह होने का आरोप लगाती आई है लेकिन चुनावों से पहले एक बार फिर बीजेपी ने सीधे ममता को निशाने पर लेते हुए उनकी तुलना हिटलर से की है।

हादसों का शहर बना कोलकाता

बासंती हाईवे से लेकर सोनारपुर तक कई एक्सीडेंट में पुलिस अधिकारी, छात्र और आम नागरिकों की गई जान

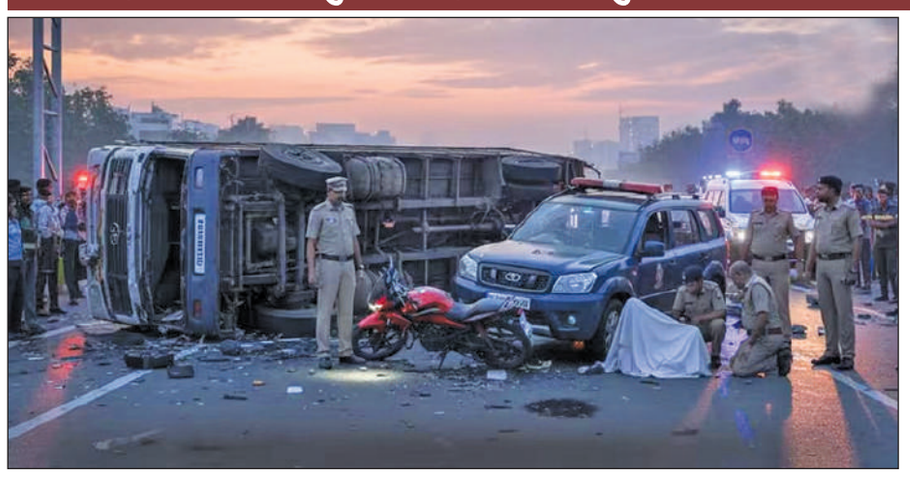

निज संवाददाता : कोलकाता हादसों का शहर बन गया है। हाल के समय में महानगर कोलकाता और आसपास के इलाकों में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। तेज रफ्तार, लापरवाही और रात के समय भारी वाहनों की आवाजाही ने हालात और चिंताजनक बना दिए हैं। पिछले कुछ दिनों में कई दर्दनाक हादसे हुए, जिनमें पुलिस अधिकारी, छात्र और आम नागरिकों की जान चली गई।

ड्यूटी से लौटते समय ट्रक की टक्कर

बीते गुरुवार रात बसंती हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ। भांगड़ डिवीजन के डीसी ऑफिस में तैनात कोलकाता पुलिस के एएसआई शाहबुद्दीन विश्वास ड्यूटी खत्म कर बाइक से घर लौट रहे थे। बैरामपुर इलाके में उनकी बाइक को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि एएसआई ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है, लेकिन चालक फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। हादसों की श्रृंखला यहीं नहीं रुकी। दो दिन पहले ईएम बाईपास पर सुबह एक बाइक सवार की मौत हुई। मृतक का नाम अलोकश हलदर (25) था। पुलिस के अनुसार युवक तेज गति से बाइक चला रहा था और हेलमेट भी नहीं पहना था। ढलाई ब्रिज से रूबी की ओर जाते समय बाइक नियंत्रण खोकर खड़ी कार से टकरा गई। अस्पताल ले जाने पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

स्कूल के छात्र को लॉरी ने कुचला

मानिकतला के बंगाल केमिकल मोड़ के पास एक और भयावह हादसा हुआ। 12 साल का छात्र पिता की बाइक पर बैठकर स्कूल जा रहा था। पीछे से आ रही लॉरी ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे बच्चा सड़क पर गिर गया और लॉरी ने उसे कुचल दिया। बच्चे को गंभीर हालत में अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ड्राइवर को फूलबागन थाने में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं, कुछ दिन पहले सॉल्टलेक में भी दुर्घटना हुई। रात करीब 10 बजे न्यूटाउन से लौटते समय एक बाइक ब्रिज के पास नियंत्रण खोकर टकरा गई। 30 साल की नेहाल वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। बाइक पर सवार दूसरा युवक अभी भी गंभीर हालत में भर्ती है।

सोनारपुर कार की टक्कर से दो किशोरों की मौत

दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। देवकुमार सरकार और सागर सरकार नाम के दो किशोर रात करीब 10:30 बजे बैडमिंटन खेलने के लिए घर से निकले थे। घासियारा के पास तेज रफ्तार कार पहले लाइट पोस्ट से टकराई। फिर एक दुकान में जा घुसी। उस समय दोनों किशोर दुकान के पास खड़े थे। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक वह नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। लगातार हो रही इन दुर्घटनाओं ने कोलकाता और आसपास के जिलों में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

आसनसोल में बालू माफियाओं के खिलाफ विरोध तेज

निज संवाददाता : आसनसोल के डामरा और तीराट इलाके में बालू माफियाओं द्वारा आसनसोल दक्षिण की भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल पर हमले की कोशिश का आरोप लगा है। इस घटना के विरोध में विधायक अग्निमित्रा पाल और उनके समर्थकों ने लगातार विरोध प्रदर्शन किया और कई स्थानों पर सड़क जाम भी किया। पुलिस की ओर से कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान तीन बैरिकेड तोड़कर भाजपा कार्यकर्ता आगे बढ़े। आरोप है कि इस झड़प में कई पुलिसकर्मी और भाजपा कार्यकर्ता घायल हुए। घटना के बाद पुलिस ने भाजपा नेता सोमनाथ मंडल, पंकज दास, संगीता नोनिया, सैकत हाजरा, संतोष भगत, मुनमुन सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। सत्तापक्ष की ओर से आसनसोल दक्षिण शहर विधानसभा के उपाध्यक्ष एवं आसनसोल नगर निगम वार्ड नंबर 6 के अध्यक्ष ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। तृणमूल कांग्रेस ने भी भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की है।

भारतीय वैज्ञानिकों ने दुनिया को चौंकाया

खोज निकाली अलकनंदा स्पाईरल गैलेक्सी

निज संवाददाता : भारतीय वैज्ञानिकों ने दुनिया को चौंका दिया है। यहां के खगोलविदों ने अंतरिक्ष के इतिहास में एक अनोखी उपलब्धि दर्ज की है। वैज्ञानिकों ने ऐसी आकाशगंगा ढूंढ निकाली है, जो तब अस्तित्व में आई थी जब पूरा ब्रह्मांड महज़ डेढ़ अरब साल पुराना था। जिस समय अंतरिक्ष में ज्यादातर संरचनाएं अस्त-व्यस्त और उथल-पुथल से भरी होती थीं, उसी दौर में यह आकाशगंगा बेहद संतुलित और सुंदर रूप में दिखाई देती है। यही बात इसे अब तक मिली शुरुआती सर्पिल आकाशगंगाओं में सबसे खास बनाती है। इस खोज का नेतृत्व पुणे के राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र की शोधार्थी राशी जैन ने किया।

उन्होंने बताया कि यह आकाशगंगा अपनी आकृति में हमारी मिल्की वे से काफी मेल खाती है। चूंकि हिंदी में मिल्की वे को 'मंदाकिनी' कहा जाता है और अलकनंदा नदी मंदाकिनी की बहन नदी मानी जाती है, इसलिए इस ''बहुत दूर की ब्रह्मांडीय बहन'' को प्रतीकात्मक रूप से अलकनंदा आकाशगंगा नाम दिया गया। यह आकाशगंगा पृथ्वी से लगभग 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और इसका आकार 30 हज़ार प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। इसकी सबसे अनूठी पहचान इसका अत्यंत व्यवस्थित रूप है। दो चमकती सर्पिल भुजाएं, केंद्र में तेज़ उजाला और पूरी संरचना में गजब का संतुलन। वैज्ञानिकों के लिए यह आश्चर्य की बात इसलिए है, क्योंकि ब्रह्मांड के शुरुआती काल में ऐसी परिपक्व संरचना मिलना लगभग असंभव माना जाता था। अब तक माना जाता था कि शुरुआती ब्रह्मांड में बनने वाली आकाशगंगाएं बेहद गर्म, टूटी-फूटी, टकरावों से भरी और किसी भी निश्चित आकार से दूर होती थीं। परंतु अलकनंदा इससे बिलकुल विपरीत निकलीयह शांत है, टिकाऊ है और बिल्कुल वैसी सर्पिल संरचना दर्शाती है जैसी विकसित ब्रह्मांड में पाई जाती है। यह खोज वैज्ञानिकों के उन सिद्धांतों को भी चुनौती देती है, जिनके अनुसार सर्पिल आकाशगंगाएं समय के बहुत लंबे विकासक्रम के बाद आकार लेती हैं। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस रहस्यमयी आकाशगंगा की उपस्थिति को उजागर किया। 2021 में लॉन्च हुआ जेडब्ल्यूएसटी लगातार शुरुआती ब्रह्मांड की गहराइयों से नई तस्वीरें भेज रहा है, जिनसे मानवता को पहली बार पता चल रहा है कि अरबों वर्ष पहले अंतरिक्ष कैसा दिखता था।

टीम के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर योगेश वाडेकर के अनुसार, अब शोधकर्ता इस आकाशगंगा के भीतर गैस और तारों की गति को विस्तार से मापेंगे। यह भी समझने की कोशिश होगी कि इसकी डिस्क ठंडी है या गर्म, और किस प्रक्रिया ने इसकी सर्पिल भुजाओं को जन्म दिया। इसके लिए जेडब्ल्यूएसटी की अगली ऑब्ज़र्वेशन और चिली स्थित एल्मा टेलीस्कोप का डेटा इस्तेमाल किया जाएगा।

अजब-गजब

डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए ब्राजील ने चुना अनोखा रास्ता

मच्छरों को पालने के लिए बना डाली दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री

निज संवाददाता : पूरी दुनिया जहां मच्छरों से छुटकारा पाने की कोशिशों में लगी है, वहीं एक देश ऐसा भी है, जिसने मच्छरों को पालने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बना डाली है। ब्राजील ने डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए एक अनोखा और वैज्ञानिक रास्ता चुना है। साओ पाउलो राज्य के कैम्पिनास शहर में बनाई गई इस फैक्ट्री में हर सप्ताह 19 करोड़ एडीज एजिप्टी मच्छर तैयार किए जा रहे हैं, जो डेंगू फैलाने वाला मुख्य प्रजाति का मच्छर है। करीब 1,300 वर्ग मीटर में फैली यह फैक्ट्री 'वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम' के तहत संचालित है। इसे बनाने का निर्णय उस समय लिया गया, जब 2024 में ब्राजील को अपने इतिहास के सबसे बड़े डेंगू प्रकोप का सामना करना पड़ा। इस साल ब्राजील में दुनिया के कुल डेंगू मामलों का 80 प्रतिशत से अधिक दर्ज हुआ, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए। यही कारण है कि देश ने इस गंभीर संकट से निपटने के लिए मच्छरों की इस विशाल परियोजना की शुरुआत की। फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे इन मच्छरों का मकसद बीमारी फैलाना नहीं, बल्कि उसे रोकना है। इसके लिए वैज्ञानिक 'वोल्बाचिया विधि' का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तकनीक के तहत मच्छरों को विकास के दौरान एक प्राकृतिक बैक्टीरिया 'वोल्बाचिया' से संक्रमित किया जाता है। यह बैक्टीरिया मच्छरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन उनके शरीर में डेंगू वायरस को विकसित होने नहीं देता। ऐसे में ये मच्छर किसी इंसान को काटें, तब भी बीमारी नहीं फैलती। इसके बाद इन्हें जंगल में छोड़ा जाता है, जहां ये स्थानीय मच्छरों के साथ प्रजनन करते हैं। प्रजनन के दौरान यह सुरक्षात्मक बैक्टीरिया उनकी संतानों में भी पहुंच जाता है। धीरे-धीरे पूरा मच्छर समुदाय वोल्बाचिया से संक्रमित हो जाता है और डेंगू फैलाने में असमर्थ हो जाता है। यह तरीका इंडोनेशिया और कोलंबिया जैसे देशों में पहले भी सफल हो चुका है, जहां डेंगू संक्रमण में 70 प्रतिशत तक की कमी देखी गई।

परिवार चलाने के लिए महिला ने अपनाया अनोखा पेशा

अपने आंसू बेचकर कमाती है लाखों रुपए

निज संवाददाता : अमेरिका में एक महिला ऐसी है, जो हर वक्त रोती है। महिला किसी दुख की वजह से नहीं रोती है, बल्कि उस महिला का यह अनोखा पेशा है। रोते समय निकलने वाले आंसुओं को यह महिला कांच की छोटी बोतलों में भरकर बेचती है। महिला को एक बोतल आंसूओं के लिए करीब 52 हजार रुपये मिलते हैं। यह काम न सिर्फ उसे आर्थिक तौर पर मजबूत बना रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर उसकी कहानी को लेकर भारी चर्चा भी हो रही है। अमेरिका के मिडवेस्ट में रहने वाली 44 वर्षीय चार बच्चों की मां लिज़ रिवर इन दिनों चर्चा में हैं। लिज़ पेशे से एक कंटेंट क्रिएटर हैं और 21 साल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं। उन्होंने खुलासा किया कि दिसंबर का महीना उनके लिए सबसे ज्यादा व्यस्त रहता है क्योंकि इसी दौरान वह सबसे ज्यादा रोती हैं, लेकिन यह रोना मजबूरी में नहीं, बल्कि ''वर्क मोड'' में होता है। उनके पास कांच के छोटे जार पहले से तैयार रहते हैं जिनमें वे अपने आंसू इकट्ठा करती हैं और बाद में इन्हें अपने प्रशंसकों को बेच देती हैं। लिज़ बताती हैं कि उनके आंसुओं की एक बोतल के बदले लोग 500 पाउंड यानी लगभग 52,000 रुपये तक देने को तैयार रहते हैं। शुरुआत में उनका यह काम बहुत धीमी गति से आगे बढ़ा था और साल में केवल दो-तीन बोतलें ही बिकती थीं, लेकिन धीरे-धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ी और अब तक वह 100 से ज्यादा जार बेच चुकी हैं। भविष्य में वह आंसुओं को माइक्रो-वर्ज़न यानी छोटे चार्म जैसी बोतलों में बेचने की योजना भी बना रही हैं। लिज़ को आंसू बेचने के अलावा अजीबोगरीब मांगों का भी सामना करना पड़ता है। कोई उनसे 20 मिनट का रोते हुए वीडियो मांगता है, तो किसी ने उनके इस्तेमाल किए गए टिश्यू या आंसुओं से भीगे तकिए का कवर खरीदने की इच्छा जताई है। वह किशोरावस्था में ही मां बन गई थीं और 23 साल की उम्र तक उनके तीन बच्चे हो चुके थे। वेट्रेस की नौकरी से परिवार चलाना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने अलग रास्ता चुना।

800 पत्थर निगलने से हुई थी एक पक्षी की दर्दनाक मौत!

12 करोड़ साल पहले की रहस्यमय सच्चाई जान सिहर उठते हैं वैज्ञानिक

निज संवाददाता : 12 करोड़ साल पहले जीवित एक छोटे पक्षी की मौत ऐसे दर्दनाक और रहस्यमयी तरीके से हुई, जिसे जानकर आज भी वैज्ञानिक सिहर उठते हैं। विज्ञान जगत को हाल ही में एक ऐसी प्रागैतिहासिक पहेली मिली है, जिसने पेलियोन्टोलॉजी और फॉरेंसिक रिसर्च दोनों के विशेषज्ञों को गहरे विचार में डाल दिया है। इस पक्षी ने एक-दो नहीं, बल्कि 800 से अधिक छोटे पत्थर निगल लिए थे, जो उसकी अंतिम सांस का कारण बने। शिकागो के फील्ड म्यूजियम की मशहूर पेलियोन्टोलॉजिस्ट जिंगमाई ओ'कॉनर और उनकी टीम ने इस 'कोल्ड केस' की जांच शुरू की, जब चीन के शेडोंग तियान्यु म्यूजियम में रखे एक अद्भुत जीवाश्म का अध्ययन किया गया। इस प्राचीन पक्षी का नाम 'क्रोमियोर्निस फंकी' रखा गया है। यह जीवाश्म विशेष प्रकार की 'लैगरस्टेट' चट्टान में संरक्षित था, जिसमें जीवों के सिर्फ अस्थियां ही नहीं, बल्कि त्वचा, पंख और मांसपेशियों के संकेत भी सुरक्षित मिलते हैं। इस पक्षी के जीवाश्म में गर्दन और पंखों के चारों ओर मौजूद नरम ऊतकों की आकृति स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन वैज्ञानिकों का ध्यान सबसे ज्यादा उसके गले में मौजूद एक बड़े उभार ने खींचा। बारीकी से जांच करने पर पता चला कि यह उभार सैकड़ों पत्थरों का घना समूह था। जब वैज्ञानिकों ने पत्थरों की गिनती की तो वे हैरान रह गए 800 से ज्यादा पत्थर इस छोटे से पक्षी की ग्रासनली में फंसे हुए थे। केवल 33 ग्राम वजन वाले इस पक्षी ने अपने शरीर के अनुपात में अकल्पनीय मात्रा में पत्थर निगले थे। जांच से पता चला कि ये पत्थर जीवाश्म चट्टान का हिस्सा नहीं थे, यानी पक्षी ने इन्हें अपनी मृत्यु से पहले ही निगला था। विज्ञान में यह तथ्य स्थापित है कि कई पक्षी 'गैस्ट्रोलिथ' नाम की प्रक्रिया के तहत पत्थर निगलते हैं, जो भोजन को पीसने में सहायक होते हैं। लेकिन इस मामले में यह सिद्धांत पूरी तरह विफल हुआ, क्योंकि क्रोमियोर्निस जिस परिवार का हिस्सा था, उसके पास भोजन पीसने वाला गिजार्ड मौजूद ही नहीं होता। इतने विशाल पत्थरों का समूह पाचन में सहायक होने की बजाय घातक साबित हुआ। फॉरेंसिक विश्लेषण के अनुसार, संभव है कि पक्षी ने पत्थरों को उल्टी के माध्यम से निकालने की कोशिश की हो, लेकिन द्रव्यमान गले में फंस गया और सांस न ले पाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 66 मिलियन वर्ष पहले हुए उस महाविनाश में यह पूरा पक्षी परिवार डायनासोरों के साथ मिट चुका था। लेकिन यह खोज हमें उस युग के जीव जगत की संवेदनशीलता और संघर्षों को समझने का अवसर देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि संभवतः पक्षी बीमार था या उसे किसी खनिज की कमी थी, जिसके कारण उसने 'पिका' व्यवहार दिखाया अर्थात अजीब चीजें खाना शुरू कर दिया। यह जीवाश्म न केवल एक दुखद मौत की गवाही देता है, बल्कि यह भी बताता है कि प्राचीन काल के जीव भी बीमारियों और जटिल व्यवहारों से जूझते थे।

पुस्तक-समीक्षा

आध्यात्मिकता, राष्ट्रवाद और सामाजिक क्रांति के अंतर्संबंधों पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक ग्रंथ

सोभन चक्रवर्ती

भूपेन्द्रनाथ दत्त जो स्वामी विवेकानन्द के छोटे भाई थे द्वारा 1954 में रचित स्वामी विवेकानंद: पैट्रियट-प्रोफेटए स्टडी एक अग्रणी प्रयास है, जिसमें विवेकानन्द के जीवन और विचारों को उन्नीसवीं शताब्दी के भारतीय राष्ट्रवाद तथा वैश्विक सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों की पृष्ठभूमि में समझने का प्रयास किया गया है। सिर्फ उनकी आध्यात्मिकता पर आधारित पारंपरिक जीवनग्रंथों के विपरीत दत्त विवेकानन्द की व्याख्या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और सामाजिक इतिहास की दृष्टि से करते हैं। पुस्तक में उन्हें केवल संन्यासी या दार्शनिक नहीं, बल्कि राष्ट्रनिर्माता, असमानता के प्रखर आलोचक और समाजवाद के प्रारम्भिक विचारक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विवेकानन्द का यह उद्घोष''भारत की आशा जनता में है''यहां एक सामाजिक क्रांति के खाके के रूप में सामने आता है, जो अनेक समाजवादी आदर्शों की पूर्व सूचना देता है। समानता, सबके लिए भोजन तथा पुरोहितवाद-विरोधये सब उनके राष्ट्रीय पुनर्जागरण के कार्यक्रम के रूप में दिखाए गए हैं।

दत्त विवेकानन्द की प्रारंभिक क्रांतिकारी सोच को भी उजागर करते हैं विशेषतः ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय राजाओं को एकजुट करने के उनके प्रयास जो बाद में शिक्षा के माध्यम से जनजागरण पर केन्द्रित हो गए। यह यात्रा उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को एक अधिक यथार्थवादी और प्रखर रूप में प्रस्तुत करती है। पुस्तक में उन्नीसवीं शताब्दी के भारत का सामाजिक परिदृश्य, पश्चिमी चिंतकों से विवेकानन्द के संवाद, उनका समाजशास्त्रीय एवं साहित्यिक दृष्टिकोण और ''प्रोलेटेरियन संस्कृति'' पर आधारित नये भारत का उनका स्वप्नइन सबकी गहन पड़ताल है। विशेष रूप से, दत्त यह दावा करते हैं कि विवेकानन्द स्वयं को ''समाजवादी'' के रूप में पहचानते थे भारतीय राजनीति में समाजवाद शब्द के प्रचलित होने से बहुत पहले उन्होंने अपने विचारों को रूस और चीन जैसे वैश्विक आंदोलनों के साथ भी जोड़ा। पुस्तक की शक्ति उसके मार्क्सवादी-समाजवादी पुनर्पाठ, विवेकानन्द की अंतरराष्ट्रीय दृष्टि, तथा वैश्विक सामाजिक परिवर्तन के प्रति उनके भविष्यवाणी-सदृश विचारों को रेखांकित करने में है। हालांकि कुछ स्थानों पर विचारधारा की छाप चयनात्मक प्रतीत होती है और शैली की घनी एवं विवादात्मक प्रकृति सामान्य पाठकों को कठिन

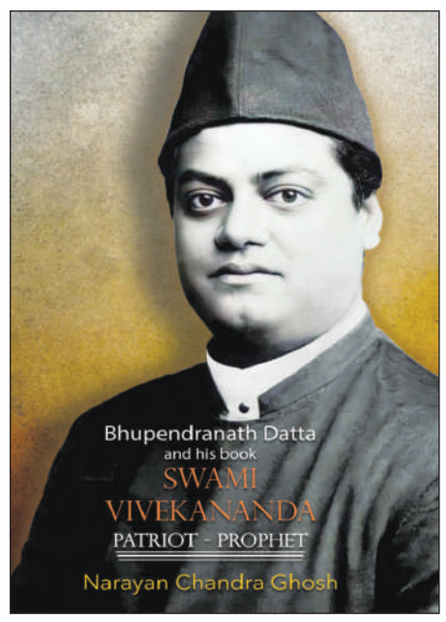

लग सकती है। कुछ दावे, विशेषकर क्रांतिकारी योजनाओं से जुड़े, ऐतिहासिक रूप से सत्यापित करना भी कठिन है। नारायणचन्द्र घोष के उत्कृष्ट निबंध एन इनविजिबल रेवोल्युशनरी: भूपेन्द्रनाथ दत्त को साथ रखने पर दोनों लेखन मिलकर एक अद्भुत द्वि-चित्र प्रस्तुत करते हैं। एक ओर विवेकानन्द एक राष्ट्रीय आदर्श और सामाजिक क्रांति के प्रवक्ता के रूप में उभरते हैं; दूसरी ओर भूपेन्द्रनाथ स्वयं ''अदृश्य क्रांति'' के जीवंत प्रतीक के रूप में सामने आते हैं। समग्रतः ये अध्ययन दत्त बंधुओं की विरासत को नए सिरे से समझने का निमंत्रण देते हैं सिर्फ आध्यात्मिक या बौद्धिक व्यक्तित्व के रूप में नहीं, बल्कि उन क्रांतिकारी स्वरों के रूप में, जिन्होंने भारत के जागरण को विश्वव्यापी सामाजिक न्याय संघर्षों से जोड़ा। आध्यात्मिकता, राष्ट्रवाद और सामाजिक क्रांति के अंतर्संबंधों में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए स्वामी विवेकानंद: पैट्रियट-प्रोफेट एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक ग्रंथ है।

भूपेन्द्रनाथ दत्त और उनकी पुस्तक स्वामी विवेकानंद: पैट्रियट-प्रोफेट
लेखक: नारायणचन्द्र घोष
प्रकाशक: मोहता पब्लिशिंग हाउस
मूल्य: 800/- सम्पर्क- 8910254112

साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम पर बदला गया लोक भवन के गेट का नाम

निज संवाददाता : साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चटर्जी के रचे वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने के जश्न को लेकर कई विवाद खड़े हो गए हैं। यह विवाद संसद में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंकिमदा संबोधन से शुरू हुआ। तृणमूल ने हर स्तर पर इसका कड़ा विरोध किया। अब बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने उसी बंकिम भावना से भरकर एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने लोकभवन के एक गेट का नाम बंकिम चंद्र के नाम पर रखा। दक्षिण-पश्चिम गेट का नाम ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा, सीवी आनंद बोस ने वंदे मातरम को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे साल कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है। लोकभवन की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, राज्यपाल ने शनिवार को वहां वंदे मातरम के उपलक्ष्य में नित्य शिखा का उद्घाटन किया। वहीं, लोकभवन के साउथ वेस्ट गेट का नाम भी ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम पर रखा गया। साहित्य सम्राट की अमर उपलब्धियों को श्रद्धांजलि देने के लिए लोकभवन में इस विषय पर रिसर्च, हायर एजुकेशन, सेमिनार, वर्कशॉप और लेखों के प्रकाशन के लिए अलग से व्यवस्था की घोषणा की गई। बंगाली भाषा और साहित्य साधना को और बढ़ावा देने के लिए सीवी आनंद बोस ने लोकभवन की ओर से वंदे मातरम अवॉर्ड की भी घोषणा की। राज्यपाल ने वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए साल भर कई कार्यक्रमों के लिए एक कोर कमेटी बनाई है। कोर कमेटी के प्रमुख डॉ. एसके पटनायक होंगे। योजना के मुताबिक, बंडेल, चुंचुड़ा यानी बंकिम चंद्र की कर्मभूमि पर खास समारोह होंगे।

वैश्विक खेल साझेदारी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण

भारतीय ओलंपिक संघ ने इटली की सीओएनआई से किया समझौता

शुभ्रांशु राय

अंतरराष्ट्रीय खेल संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) और इटली की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (सीओएनआई) ने पिछले दिनों नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता खिलाड़ी विकास, तकनीकी विशेषज्ञता, खेल विज्ञान तथा दोनों देशों के उच्च-प्रदर्शन प्रशिक्षण केंद्रों तक साझा पहुंच सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने का लक्ष्य रखता है। आईओए मुख्यालय में आयोजित समारोह में भारत और इटली के कई प्रतिष्ठित नेताओं की उपस्थिति रही। इटली के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री एंतोनियो तजानी ने इटली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जबकि भारत की ओर से युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया उपस्थित थे। आईओए अध्यक्ष डॉ. पी.टी. उषा और सीओएनआई अध्यक्ष लूसियानो बुओनफिग्लियो ने अपने-अपने संगठनों की ओर से औपचारिक रूप से एमओयू पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के अधिकारियों ने इस समझौते को एक दूरदर्शी कदम बताया, जो प्रतिभा विनिमय, कोचिंग उन्नयन और संयुक्त खेल कार्यक्रमों के लिए

नए रास्ते खोल सकता है। आईओए के अनुसार, यह एमओयू संयुक्त प्रशिक्षण शिविरों, खेल चिकित्सा व खेल विज्ञान विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, तथा भारतीय खिलाड़ियों को इटली के विश्व-स्तरीय उच्च-प्रदर्शन केंद्रों में प्रशिक्षण के बेहतर अवसर प्रदान करेगाजो एथलेटिक्स, फेंसिंग, साइकलिंग, स्विमिंग और शीतकालीन खेलों जैसी विधाओं में अपनी उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध हैं। कार्यक्रम में बोलते हुए तजानी ने इस समझौते को ''दो राष्ट्रों के बीच खेल के प्रति साझा जुनून से जुड़ी मित्रता का पुल'' बताया और वैश्विक खेल सहयोग को बढ़ाने के प्रति इटली की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

डॉ. मांडविया ने कहा कि यह साझेदारी भारत की दीर्घकालिक खेल दृष्टि के अनुरूप है, जो अंतरराष्ट्रीय खेल परिदृश्य में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने और खिलाड़ियों को वैश्विक एक्सपोजर प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। महान धाविका और आईओए अध्यक्ष डॉ. पी.टी. उषा ने यह रेखांकित किया कि ऐसे सहयोग ''भारत के उभरते खेल परिदृश्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण'' हैं, क्योंकि वे उन्नत प्रशिक्षण पद्धतियों तक पहुंच प्रदान करते हैं और खिलाड़ियों को ओलंपिक सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद करते हैं। सीओएनआई अध्यक्ष लूसियानो बुओनफिग्लियो ने भी इन विचारों का समर्थन किया और विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल दोनों देशों के खिलाड़ियों और कोचों को लाभान्वित करेगी। एमओयू में संयुक्त कार्यशालाओं, खेल प्रशासन कार्यक्रमों और शासन व एंटी-डोपिंग ढांचे में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के आदान-प्रदान का प्रावधान भी शामिल है। खेल विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रकार का सहयोग भारत की बढ़ती खेल आधारभूत संरचना और इटली की उत्कृष्ट प्रशिक्षण विशेषज्ञता को मिलाकर खिलाड़ियों के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार ला सकता है। यह समझौता भारत और इटली के बीच गहरे खेल सहयोग की एक आशाजनक शुरुआत का प्रतीक है, जो वैश्विक प्रतिभा को निखारने और ओलंपिक भावना को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोनों देश आगे की ओर देखते हुए उम्मीद कर रहे हैं कि यह साझेदारी खिलाड़ियों के लिए नए अवसर खोलेगी और खेल के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त करेगी।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

बिना ब्याज व गारंटी के योगी सरकार दे रही 5 लाख तक का लोन

- 18 से 40 वर्ष के युवा विशेष रूप से लाभान्वित
- 10 प्रतिशत तक अनुदान भी उपलब्ध

निज संवाददाता : उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में पांच लाख रुपये तक का ऋण बिना ब्याज एवं बिना गारंटी प्रदान किया जा रहा है। 10 प्रतिशत तक अनुदान भी उपलब्ध है। सामान्य वर्ग के लिए 15 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 12.5 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए 10 प्रतिशत मार्जिन मनी निर्धारित की गई है।

विकास भवन हर्षवर्धन सभागार में सीएम युवा योजना, लखपति दीदी कार्यक्रम व आरसेटी से संबंधित विभागीय कार्यशाला का आयोजन उपायुक्त एनआरएलएम राज कुमार लोधी, उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र धनंजय सिंह व अग्रणी जिला प्रबंधक अमरेन्द्र कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अग्रणी जिला प्रबंधक ने निर्देश दिए कि सभी बीएमएम एवं सीएफएल टीमें अधिक से अधिक युवाओं को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से लाभान्वित कराने के लिए प्रेरित करें। डीसी एनआरएलएम ने सभी बीएमएम को निर्देश दिए कि प्रत्येक माह कम से कम पांच पांच लखपति दीदी को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से आच्छादित किया जाए। उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र ने कहा कि हर कदम उद्यमिता की ओर, हर युवा आत्मनिर्भरता की ओर की भावना के साथ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान संचालित किया जा रहा है। 18 से 40 वर्ष तक आयु वर्ग के युवाओं को यह योजना विशेष रूप से लाभान्वित कर रही है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का कक्षा आठ पास होना, संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त होना तथा न्यूनतम पांच दिवस का प्रशिक्षण पूर्ण होना आवश्यक है।

मेसी के कार्यक्रम में नाराज फैंस ने की तोड़फोड़

- साल्टलेक स्टेडियम में फेंकी कुर्सियां और बोतलें
- सीएम ममता बनर्जी ने मांगी माफी, जांच का दिया आदेश

निज संवाददाता : कोलकाता के सॉल्टलेक स्टेडियम में फुटबॉल सुपरस्टार लियोनल मेसी के कार्यक्रम से जल्दी जाने के बाद नाराज फैंस ने जमकर तोड़फोड़ की। बीते रविवार को स्टेडियम में हुए इस हंगामे और अव्यवस्था पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गहरा दुख और हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि स्टेडियम में जिस तरह का कुप्रबंधन देखने को मिला, उससे वह बेहद आहत हैं। सीएम ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले की जांच के लिए जांच समिति बनाने का भी एलान किया है। बता दें कि कोलकाता के सॉल्टलेक स्टेडियम में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब फुटबॉल सुपरस्टार लियोनल मेसी के अचानक स्टेडियम छोड़ने के बाद नाराज फैंस भड़क उठे। अपने जी.ओ.ए.टी दौरे पर भारत पहुंचे मेसी को देखने हजारों दर्शक भारी कीमत पर टिकट लेकर पहुंचे थे। लैप ऑफ ऑनर के बाद मेसी के जल्दी निकलते ही फैंस ने कुर्सियां और बोतलें फेंककर विरोध जताया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह खुद भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्टेडियम जा रही थीं। वहां हजारों की संख्या में खेल प्रेमी और फुटबॉल स्टार लियोनल मेसी के फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ी की एक झलक पाने के लिए जुटे हुए थे। ममता बनर्जी ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए लियोनल मेसी और सभी खेल प्रेमियों से माफी मांगी। ममता बनर्जी ने अपने पोस्ट में आगे कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे सभी प्रशंसकों की भावनाएं आहत हुई हैं।इस दौरान मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच समिति गठित करने का एलान किया है। बनर्जी ने बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस अशिम कुमार रे करेंगे। समिति में राज्य के मुख्य सचिव और गृह व पहाड़ी मामलों के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी सदस्य होंगे। गौरतलब है कि यह समिति पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए सुझाव देगी। मेसी के एक फैन ने गुस्से में कहा-मेसी के चारों तरफ सिर्फ नेता और अभिनेता थे। हमें क्यों बुलाया गया? हमने 12 हजार रुपये की टिकट ली, लेकिन उनका चेहरा तक नहीं देख पाए।

आयोजक गिरफ्तार

साल्टलेक स्टेडियम में शनिवार को प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनल मेसी के कार्यक्रम के दौरान अव्यवस्था पर पुलिस ने एक्शन लिया है। मुख्य आयोजक सतादु दत्ता को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। डीजी राजीव कुमार ने दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भरोसा दिया। डीजी ने कहा कि दर्शकों के टिकट के पैसे वापस किए जाने चाहिए। राजीव कुमार ने कहा-फैंस में किसी तरह का गुस्सा या बेचैनी थी, जो कह रहे थे कि वह नहीं खेल रहे हैं।उन्होंने कहा कि प्लान यह था कि वह यहां आएंगे, हाथ हिलाएंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे और चले जाएंगे। अब सरकार ने पहले ही एक कमेटी बना दी है जो सभी पहलुओं को देखेगी, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या ऑर्गनाइजर की तरफ से कोई मिसमैनेजमेंट हुआ था या कुछ और।उन्होंने कहा कि ऑर्गनाइजर उन लोगों को लिखकर दे रहा है। जिन्हें चिंता है कि जो टिकट बिक चुके हैं, उन्हें रिफंड किया जाना चाहिए। अब स्थिति कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि हम यह पक्का करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं कि यह मिसमैनेजमेंट बिना सजा के न रहे।

एक अन्य फैन ने कहा-यह बिल्कुल खराब आयोजन था। मेसी सिर्फ 10 मिनट के लिए आए और चले गए। उन्होंने न तो एक किक मारी और न ही पेनल्टी ली। हमारे पैसे, भावनाएं और समय सब बर्बाद हो गया। फैंस का आरोप है कि मेसी के चारों ओर सिर्फ नेता और मंत्री मौजूद थे, जबकि आम दर्शकों को उनसे दूर रखा गया।

इस वजह से स्टेडियम में मौजूद हजारों लोग उन्हें ठीक से देख भी नहीं पाए। नाराज फैंस ने यह भी कहा कि आयोजनकर्ताओं ने शाहरुख खान के आने का वादा किया था, लेकिन वह भी पूरा नहीं किया गया। एक फैन ने कहा-शाहरुख खान भी आएंगे, ऐसा कहा गया था लेकिन किसी को नहीं लाया गया। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के सॉल्टलेक स्टेडियम में मैदान में आते ही हालात बेकाबू हो गए। स्टेडियम में फैली अव्यवस्था और अराजकता के चलते कार्यक्रम को बीच में ही रोकना पड़ा, जिससे मेसी की कई प्रमुख हस्तियों से तय मुलाकात भी नहीं हो सकी। अराजक हालात के कारण स्टेडियम में मौजूद बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी से मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं दूसरी ओर सॉल्टलेक स्टेडियम में हुए हंगामे को लेकर भाजपा सांसद सुकांत मजूमदार ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर तीखा हमला बोला है।

मनोरंजन

'महाकाली' के पोस्टर में अक्षय खन्ना के लुक ने सबको चौंकाया

रहमान डकैत के बाद शुक्राचार्य बनकर बॉक्स ऑफिस पर मचाएंगे तहलका

निज संवाददाता: धुरंधर की रिलीज के बाद अक्षय खन्ना लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। हर तरफ उनके ही चर्चे हैं। इस फिल्म में उनके निभाए किरदार रहमान डकैत की दर्शक और समीक्षक दोनों ही जमकर तारीफ कर रहे हैं। हर तरफ सिर्फ अक्षय के दमदार परफॉर्मेंस की चर्चा हो रही है। इसी बीच प्रशांत वर्मा की सुपरहीरो फिल्म 'महाकाली' से अक्षय खन्ना का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया। पोस्टर सामने आते ही इंटरनेट पर तहलका मच गया है। 'महाकाली' के पोस्टर में अक्षय खन्ना के लुक ने सबको चौंका दिया। प्रशांत वर्मा ने शुक्राचार्य बने अक्षय खन्ना का लुक शेयर करते हुए लिखा-देवताओं की छाया में, विद्रोह की सबसे चमकदार लौ उठी। पेश है रहस्यमयी अक्षय खन्ना, शाश्वत 'असुरगुरु शुक्राचार्य' के रूप में। पोस्टर में अक्षय एक पत्थर के किले के सामने खड़े हैं। उन्होंने लंबा काला चोगा पहन रखा है और उनकी एक आंख चांदी की तरह चमक रही है जो इस लुक को और भी डार्क और पॉवरफुल बनाती है। पोस्टर में अक्षय एक बिल्कुल अलग अवतार में दिख रहे हैं। भारी मेकअप के साथ उन्हें एक ऋषि जैसा रूप दिया गया है। लंबी दाढ़ी, लहराते बाल और ऋषि जैसी रहस्यमयी झलक उनके लुक को और भी प्रभावशाली बना रहे हैं। उन्हें देख कर पहचानना मुश्किल हो रहा है। 'महाकाली' का निर्देशन पूजा अपर्णा कोल्लरु कर रही हैं। वह इस फिल्म से डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रही हैं। आरकेडी स्टूडियोज द्वारा प्रोड्यूस की जा रही इस फिल्म में प्रशांत वर्मा क्रिएटर और को-राइटर हैं। फिल्म फिलहाल प्रोडक्शन में है। म्यूजिक स्मरण साई और सिनेमैटोग्राफी सुरेश रागुतु द्वारा की जा रही है।

गुमनामी की जिंदगी जी रही एक्ट्रेस 'प्रिया गिल'

निज संवाददाता : अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री प्रिया गिल आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। 1999 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म 'सिर्फ तुम' में अभिनय के बाद अभिनेत्री प्रिया गिल अचानक रातोंरात स्टार बन गई थीं, लेकिन समय के साथ वह फिल्मी दुनिया से दूर होती चली गईं। एक्ट्रेस आज पूरी तरह गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाली प्रिया गिल ने इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों शाहरुख खान और सलमान खान के साथ भी काम किया, लेकिन मायूसी और संघर्ष ने उन्हें कैमरे की चमक से बहुत दूर कर दिया। प्रिया गिल ने 1995 में मिस इंडिया प्रतियोगिता में फाइनलिस्ट बनकर मनोरंजन जगत में कदम रखा।

यूपी पंचायत जंग से पहले कांग्रेस-सपा का साथ टूटा

2027 की लड़ाई के संकेत साफ

स्वदेश कुमार

उत्तर प्रदेश की सियासत में वह जोड़ी जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी, अब पंचायत चुनाव के ठीक पहले टूट चुकी है। ''दो लड़कों की जोड़ी'' कहे जाने वाले राहुल गांधी और अखिलेश यादव की दोस्ती जिस तेजी से परवान चढ़ी थी, उसी तेजी से अब दूरियां भी बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस ने तय किया है कि 2026 में होने वाले ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनाव वह पूरी तरह अपने दम पर लड़ेगी। इस फैसले के पीछे सिर्फ राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव की मजबूत तैयारी छिपी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, और सभी सांसदों के साथ दिल्ली में हुई बैठक के बाद एक स्पष्ट संदेश दिया गया अब यूपी में संगठन को जड़ों से मजबूत किया जाएगा और हर बूथ, हर गांव में कांग्रेस की अपनी पहचान बनेगी। पार्टी का मानना है कि गठबंधन में रहकर छोटे कार्यकर्ताओं को अवसर सीमित हो जाते हैं। पंचायत चुनाव सिंबल पर भले न होते हों, लेकिन गांव की राजनीति का आधार इन्हीं चुनावों से तैयार होता है। कांग्रेस इसी जमीन को फिर से हासिल करना चाहती है, जिसे 1990 के दशक के बाद वह लगातार खोती गई। उत्तर प्रदेश में कुल 57,694 ग्राम पंचायतें हैं। इन पंचायतों में ग्राम प्रधानों और लगभग साढ़े सात लाख से अधिक पंचायत सदस्यों का चुनाव होना है। इनके अलावा 74,345 क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने जाएंगे, जो आगे चलकर 826 ब्लॉक प्रमुखों के लिए मतदान करेंगे। जिला स्तर पर 3,011 जिला पंचायत सदस्य चुनकर आगे जिला पंचायत अध्यक्ष के पद का फैसला

करेंगे। इन सभी चुनावों की तैयारी अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच मानी जा रही है। ग्रामीण इलाकों में इन चुनावों की गूंज विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा होती है, क्योंकि यहां की राजनीतिक रिश्तों, जातीय समीकरणों और स्थानीय पकड़ पर आधारित रहती है। इसीलिए पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। कांग्रेस के अंदर यह बात साफ है कि यदि पंचायत चुनावों में 10 से 12 जिले भी ऐसे निकल आए जहां जिला पंचायत सदस्य ज्यादा संख्या में जीत हासिल कर लें, तो विधानसभा टिकट वितरण में पार्टी की मोलभाव की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें दी थीं। कांग्रेस को भरोसा है कि अब आंकड़े बदलेंगे और सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए यह चुनाव उसके लिए बहुत बड़ा मौका है। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी ने पहले से ही पंचायत चुनाव से एक कदम पीछे खींच लिया था। संगठन के भीतर उनका तर्क था कि पंचायत चुनाव में सपा कार्यकर्ताओं को अक्सर प्रशासनिक दबाव का सामना करना पड़ता है और परिणाम अपेक्षित नहीं आते। सपा स्थानीय चुनावों में अपनी ऊर्जा को विधानसभा 2027 तक बचाना चाहती है। इसी दूरी ने कांग्रेस को यह समझा दिया कि यदि अभी भी साझेदारी में रही तो अपना कोई खास विस्तार नहीं हो पाएगा। यही वजह रही कि अब अकेले चलने की रणनीति पर मुहर लग गई। केवल कांग्रेस ही नहीं, बल्कि भाजपा के सभी सहयोगी दल अपना दल (एस), आरएलडी, निषाद पार्टी और सुभासपा ने भी पंचायत चुनाव अपने दम पर लड़ने का ऐलान पहले ही कर दिया है। यह अपने-अपने जातीय आधार को गर्म रखने और कार्यकर्ताओं को ज्यादा टिकट देने की नीति है। भाजपा भले शासन में हो, लेकिन सहयोगी दलों की इच्छा होती है कि उनके वोटर समझें कि दल स्वतंत्र भी है, सिर्फ सहारे पर नहीं टिका। यही सोच कांग्रेस ने भी अपनाई है। पंचायत चुनाव की राजनीति सीधे-सीधे जाति और जमीन के समीकरणों पर निर्भर होती है। जहां कुर्मी बहुल इलाकों में अपना दल मजबूत होती है, वहीं पूर्वांचल में निषाद समाज पर संजय निषाद की पकड़ रही है। पश्चिम यूपी में जाट-गुर्जर मतदाताओं पर आरएलडी का प्रभाव है। कांग्रेस इस जातीय नक्शे को नए सिरे से देख रही है और दावा कर रही है कि वह जाति से ऊपर विकास और संविधान की रक्षा की राजनीति करेगी। लेकिन जमीनी सच यह है कि बिना जातीय जोड़तोड़ के पंचायत चुनाव जीतना लगभग नामुमकिन है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपनी निष्क्रिय हो चुकी पंचायत स्तरीय इकाइयों को जागृत करना।

'बजरंगी भाईजान' की मुन्नी अब हो गई है बेहद ग्लैमरस

हर्षाली मल्होत्रा की तस्वीरों ने लोगों का दिल जीता

निज संवाददाता : सलमान खान की फिल्म 'बजरंगी भाईजान' की छोटी मुन्नी जिसे हम सबने कभी मासूम आंखों और प्यारे अंदाज में देखा, अब बड़ी होकर ग्लैमरस और आकर्षक अवतार में सामने आई हैं। उनका ये नया लुक देखने वाले हर किसी को हैरान कर देता है और फैंस के बीच चर्चा का नया कारण बन चुका है। सलमान खान की सुपरहिट फिल्म 'बजरंगी भाईजान' में छोटी मुन्नी के रोल से फेमस हुई हर्षाली मल्होत्रा आज पूरी तरह बदल चुकी हैं। उस मासूम और इनोसेंट बच्ची ने अब एक ऐसी गॉर्जियस और ग्लैमरस यंग लेडी बन गई है, जिसे देखकर फैंस हैरान रह जाते हैं। हर्षाली का ट्रांसफॉर्मेशन वाकई में देखने लायक है। जब हर्षाली ने फिल्म में एक्टिंग की थी, तब उनका फेस सिर्फ मासूमियत और इनोसेंस से भरा था। लेकिन अब उनका लुक मैच्योरड, स्टाइलिश और बहुत ही एलीगेंट हो गया है। उनका कॉन्फिडेंस और फैशन सेंस उनके हर फोटो में साफ नजर आता है। चाहे वो ट्रेडिशनल आउटफिट पहनें या कैज़ुअल चिक ड्रेसेस, हर अंदाज में उनका लुक बेहद ग्रेसफुल और ट्रेंडी लगता है। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं, और फैंस उनके ग्लो, ब्यूटी और स्टाइल की तारीफ करते नहीं थकते हैं। हर्षाली का फेस अब मैच्योरड हो गया है, लेकिन उनके मासूम एक्सप्रेशन्स अभी भी उनके चार्म को मेन्टेन करते हैं। उनके नए फोटोशूट्स में उनका ग्लैमर, स्टाइल और कॉन्फिडेंस एकदम नेक्स्ट लेवल का नजर आता है। लोगों ने उनके नए लुक को खूब पसंद किया है। सलमान खान की छोटी मुन्नी अब इतनी स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट यंग लेडी बन चुकी है कि उनके ग्लैमरस नए अवतार ने सबको इम्प्रेस कर दिया है। हर्षाली का ये ट्रांसफॉर्मेशन साबित करता है कि एक इनोसेंट चाइल्ड आर्टिस्ट भी समय के साथ एक कॉन्फिडेंट, गॉर्जियस और ट्रेंड सेटिंग स्टार बन सकती है। फैंस उनके नए लुक्स और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बेहद इक्साइटड हैं।

स्वामी मोहता पब्लिशिंग हाउस के लिए, प्रकाशक, मुद्रक : अजय कुमार मोहता द्वारा अरिहंत मुद्रा, 61, सूर्यसेन स्ट्रीट, कोलकाता-700009 से मुद्रित एवं प्रकाशित। **संपादकीय कार्यालय** : 10, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सरणी, (क्लाइब रो), 5बी मंजिल, रूम नं. 9, कोलकाता-700001, **स्थानीय कार्यालय** : 28-5 कन्वेंट रोड, मौलाली, कोलकाता-700014। **संपादक : अजय कुमार मोहता**, मो. 9830045693, E-mail-gambheersamachar@gmail.com. Website. www.gambheersamachar.in (प्रकाशित रचनाओं के चयन, संपादन हेतु पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी, सभी कानूनी विवाद के लिए कोलकाता न्याय क्षेत्र)